STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of recommendations contained in the Hundred and Nineteenth Report of Department-Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, I lay a statement on the status of the implementation of recommendations contained in the Hundred and Nineteenth Report of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at twenty nine minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty one minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

SHORT DURATION DISCUSSION

Suicide by the farmers in various parts of the country and the demand to increase the Minimum Support Price of foodgrains

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Short Duration Discussion. Dr. M.S. Gill.

श्री एम0 वेंकैया नायडु (कर्णाटक): सर, विपक्ष को पहले बोलने का मौका देना चाहिए?

श्री उपसभापति : शॉर्ट ड्यूरेशन में जो फर्स्ट नाम रहता है, उसको बोलना होता है।

डा0 एम0 एस0 गिल (पंजाब): सर, वह मानते हैं कि मैं बोलूंगा, हम एक ही बात करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It was discussed in the morning. यह बात डिसकसन के दौरान आई थी।

डा0 एम0 एस0 गिल : उपसभापति जी, मैं धन्यवाद देता हूं, कि आपने यह विषय चर्चा के लिए रखा ओर मुझे इसको शुरू करने का मौका भी दिया। मेरा ख्याल है कि यह बात तो सारा सदन, चाहे वह किसी तरफ के सदस्य हों, मानेंगे और राजनाथ सिंह जी किसान हैं, वह जानते हैं, वह थोड़ी-बहुत किसानी करते भी होंगे, यह देश तो अब भी किसान के ऊपर निर्भर है। इंडस्ट्री बढ़ी है, लिबरलाइजेशन हुआ है, आई0टी0आई0 है, बहुत कुछ हुआ है, हम इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन आज भी 65 प्रतिशत या उससे कुछ ज्यादा लोग गांवों में बैठे हैं, चाहे

दक्षिण हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, कोई भी प्रदेश हो। अगर उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, इतना इकोनोमिक्स मैं जानता हूं, अगर उनको साथ लेकर उठा नहीं सकेंगे, तो कोई देश इक्कीसवीं सदी में, एशिया की सेंचुरी या इंडिया की सेंचुरी बनने का नहीं है, यह मैं स्पष्ट कहता हूं। ...**(व्यवधान)**... अहलुवालिया जी, मेरी भी थोड़ी गल सुन लो। ...**(व्यवधान)**... यह जो देश है, यह गांव वालों के, किसानों के, सारे ही जो रूरल लोग हैं, उनके बगैर, किसी सदी में, किसी पहली कतार में नहीं आयेगा, ऐसा मैं मानता हूं। आज सबको यह पता है, सारे ही इस बात पर दुखी हैं कि किसान की हालत बुरी है और बिगड़ी है, बेहतर नहीं हुई है। जो आत्महत्यायें हो रही हैं, लोग आन्ध्र प्रदेश की रोज़ बात करते हैं, मैंने भी यहां कई दफा की है, आन्ध्र प्रदेश की बात की है और अन्य कई प्रांतों की बात की है। मैंने यह बात कही कि पंजाब में भी स्यूइसाइड्स हुई हैं, अगर कोई कहता है कि पंजाब सरकार ने कोई फिगर्स नहीं दी है, तो इससे बात खत्म नहीं होगी। मैं अमृतसर में, गांव में बैठा हुआ हूं, जलसा हो रहा है और मेरे साथ बैठे हुए किसान कह रहे हैं, किसान यूनियन के लोग कह रहे हैं कि फलां गांव में 42 साल के आदमी ने आत्महत्या कर ली है, उसके दो लड़कियां 15 साल और 17 साल की हैं, कौन रोटी देगा, कौन शादी करेगा? ऐसी हालत है। अगर पंजाब में यह है, तो बाकी हिन्दुस्तान का अंदाजा करने की जरूरत ही नहीं है। वह जो हरित क्रांति 1970 में गेहूं के साथ आई थी और बाद में धान का आया था, मैं उस काम में बड़ा हिस्सेदार हूं। लेकिन आज अगर पंजाब में यह नीचे गिर गया है, हरियाणा में गिर गया है, यू0पी0 में गिर गया है, तो आन्ध्र प्रदेश मैंने बहुत घूम कर देखा है, वह तो सारा पत्थर का देश है। आई0टी0 हैदराबाद में है, मैंने एक दफा नायडु जी को कहा था, जितनी मर्जी कर लो, अगर डेमोक्रेसी है, अगर गांव में कुछ नहीं होगा, अगर वोटर नहीं होगा, लोग मरेंगे, मैंने टी0वी0 पर देखा कि लड़की को कहती है मां कि मैं दस साल की यह दे रही हूं, क्योंकि मैं चार बच्चे पाल नहीं सकती। मेरा दिल आज भी कांपता है इस पर कि क्या हुआ, लोग ऐसा भी करते हैं? क्या ऐसा मां को करना पड़ता है। यह हालत देश की है। इसलिए आत्महत्या भी हैं, कई प्रांतों में हैं और वे इसलिए हैं कि स्मॉल होल्डिंग्ज़ का यह देश है, पंजाब में भी दो एकड़ वाले हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं भी दो एकड़ वाला हूं और आजादी के समय हम 30 करोड़ थे अब हम 100 करोड़ से ऊपर हो गये हैं, तो वह तो कट, कट, कट सारे प्रांतों में हुआ है। दो एकड़, तीन एकड़, चार एकड़ में, उनका इकोनामिक होल्डिंग, यहां उनकी इन्कम बनती ही नहीं है। अगर नहीं बनती है तो उसके ऊपर कैसे गुजारा होगा? उनको भी हमने रोटी तो देनी ही है। उनको रोटी देनी है, तो थोड़ी सी इज्जत की दो, ज्यादा मत दो। अमीर तो और हिन्दुस्तान में होंगे, रूरल में नहीं होंगे, न कभी थे, न दुनिया में कहीं हैं। जो अमीर होते हैं, बिलियनेयर, जिनकी आज इस देश में बहुत गौरव से चर्चा होती है कि कितने बिलियनेयर इंडिया में हो गए। टीवी वाले या प्रेस वाले एक ही खबर देते हैं कि कितने हो गए हैं, कितने और होंगे। सारे लंदन में छुट्टियां काटेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। लेकिन हिन्दुस्तान तो इधर ही रहेगा - जो असल हिन्दुस्तान है और आज भारत और इंडिया का सवाल बन रहा है। यह देश अगर इकट्ठा नहीं जाएगा, तब भी मुश्किल होगी, आप जो मर्जी कर लो। पंजाब में सेंवटीज़ में जो कुछ हुआ था, यह मत सोचो कि दोबारा नहीं आ सकता है - मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। मैं इस हाउस में यह भी कह चुका हूं कि हिन्दुस्तान के पेट में नेपाल से लेकर कर्नाटक तक तो एक आग लगी ही हुई है, सबको पता है। वह प्रॉब्लम सिर्फ नयी बटालियन से तो डील नहीं होगी, जितनी मर्जी बटालियन खड़ी कर लो। वह तो सोशल और सॉल्यूशन से ही होगी, उसके लिए रोटी देनी होगी। जब तक हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जहां

डेमोक्रेसी टूट नहीं सकती क्योंकि लोगों को विश्वास है, इसलिए जो मर्जी कर लो, सबको साथ जाना होगा, सबको रोटी देनी होगी। ठीक है, आप घी से खाओ, मैं सूखी खा लूं, किन्तु सूखी तो दोगे। अगर नहीं दोगे तो बलवा होगा। यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, मुझे खुशी है कि वे इन चीज़ों को सुनेंगे और इन पर सोचेंगे। इस हिसाब से जो भी आप पॉलिसी बनाते हो, चाहे इनवेस्टमेंट की हो, चाहे क्रेडिट की हो - ग्रीन रेवोल्यूशन जितना पंजाब में था, पंजाब ने 60 परसेंट सरप्लस इस देश को दिया है, पिछले बीस-तीस साल से, सन् 70 से लेकर, सबको पता है, इनके पास फिगर्स हैं, मैं भी उनके साथ रहा हूं, धान का भी और गंदम का भी। लेकिन वह सारा कुछ हमने कोऑपरेटिव क्रेडिट में बनाया था। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मीडियम टर्म, शॉट टर्म, क्रॉप लोन - यह सब मुझसे पूछो। मैंने किताब भी लिखी है, विलायत में, केम्ब्रिज में जाकर, पंजाब के ऊपर और इंडिया के ऊपर। आपको भी पता है। आज पंजाब में कोऑपरेटिव क्रेडिट बीस परसेंट है। रोज़ चीफ मिनिस्टर फिगर्स देता है कि उसमें से 26 हजार करोड़ कर्जा है, किसान का और उसमें से मेन फिगर है, साहूकार क्रेडिट की। मैंने जब किताब लिखी थी, लॉर्ड कर्ज़न, 19वीं शताब्दी से लेकर इंडिया का स्टडी किया था। इस प्रकार साहूकार क्रेडिट से बचाने के लिए कोऑपरेटिव सिस्टम वे बाहर से लाए थे, वेस्ट से लाए थे, इटली से, डेनमार्क से और लेबर पार्टी के केयर हार्डी वगैरह इंग्लैंड से। अब वह खत्म हो गया है, सारे देश में हो गया है। मुझे पता है, उसमें कई दिक्कतें हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जानते हैं। सॉल्यूशन मैं भी एक दम देने वाला नहीं हूं, न ही दे सकता हूं। लेकिन चिंता तो हो, इलाज तो करना पड़ेगा कि चीप क्रेडिट हो। जो प्राइस उसको दो, वह नेट इनकम हो - जो मैं पंजाब में रोज़ कह रहा हूं, अभी धान की कीमत के ऊपर कि आप सच्चे दिल से हिसाब कर लो और उसके खर्चे लेकर, डीज़ल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की और ऑयल की कीमत के बारे में आप जानते ही हैं कि इराक के बाद कहां वह जा रही है। इस प्रकार उसका जो भी हिसाब करो, वह सच्चे दिल से करो, गप-शप से नहीं। Agricultural Commission for Costs and Prices है, मैं भी वहां का सेक्रेटरी हूं। वह तो सबॉर्डीनेट्स हैं। मैं यह कहूंगा, मैंने पंजाब में कहा है, इंडीपेंडेंट एग्रीकल्चरल प्राइस कमिशन हो, outside the Ministry. It should have powerful, independent people, experts as well as farmers, not just economists, who think of balancing budgets or think of some other factors or, purely the distribution side for those who are not there, for those living in the urban areas. उनको सब्सिडी दो, लेकिन वह मेरी जेब से कैसे निकालोगे और आज तो मेरी जेब में है ही कुछ नहीं। तब क्या करेंगे? इसलिए मैं आप लोगों से अर्ज करता हूं कि इस संबंध में इधर बैठने वाले भी और उधर बैठने वाले भी गंभीरता से सोचें। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि शरद पवार जी को इस संबंध में बहुत तजुर्बा है, मैं भी पिछले चालीस साल से इधर-उधर से उनके नज़दीक ही रहा हूं, चाहे मैं जिस ड्यूटी में भी रहा हूं। मैं यह जानता हूं कि अगर ये सोच सकते, तो ये किसान का सोच सकते हैं, उधर का भी सोच सकते हैं और इधर का भी। हम लोग आज प्रधानमंत्री जी के पास गए। मैंने आज उन्हें कहा कि सुसाइड का चार-पांच सदर्न स्टेट्स का ही हुआ - वहां प्रॉब्लम है, लेकिन पंजाब के संबंध में अच्छा नहीं लगा कि पंजाब में हो रहे सुसाइड्स के कोई मायने ही नहीं हैं। 30-40 साल से वह अनाज दे रहा है और आज भी आप वहां से पचास लाख टन गंदम तो शायद ला रहे हो, और भी लाओगे। आज भी कहते हो कि अब जल्दी ग्रो करो। मेरी नौकरी इसी पोज़िशन में गयी, मैं पीछे के सबके गिन सकता हूं, अगर आप कभी मुझे कहेंगे। उसमें जब थोड़ा सा सरप्लस हो जाए तो यहीं मीटिंग्स में

हमें कह दिया जाता था कि 'No, we are not bothered about wheat, we cannot give you more price.' दुकरा दिया जाता था और मैंने यह भी देखा - प्लानिंग कमीशन के एक फॉर्मर सेक्रेटरी थे - मिस्टर राव, आज भी होंगे। वे जब वहां आते हैं, तो कहते हैं कि तुमको कॉटन नहीं पैदा करनी, तुमको तो व्हीट ही करना है, क्योंकि हमें तो व्हीट ही चाहिए। हरेक आदमी, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे किसान हो, वह काम वही करेगा, जिसमें उसको थोड़ा सा लाभ हो। तो यह तो नहीं हो सकता और फिर इतने सरप्लस के बाद अब वह सरप्लस निकल गया, अब चिंता हो रही है और अगर हमसे चाहते हो, तो यह जो धान की कीमत है, पिछले चार साल के मैं टेबल देख रहा हूं - दस रुपए, ज़ीरो, दस रुपए, दस रुपए। मैंने पंजाब में डटकर कहा कि यह तो चाय की प्याली की भी कीमत नहीं है। तो जो reasonable है, मैं कहता हूं सच्चे दिल से उसका हिसाब करो और सच्चे दिल से उसको दे दो।

The second thing that I want to say कि व्हीट के मामले में जो हुआ, थोड़ी कीमत दी, लेकिन बाद में एक बोनस डिक्लेयर कर दिया। यह बोनस का आइडिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। It is a clever device of Government people in Delhi, because अगर प्राइस बोलोगे, तो फिर parameter वहां चला जाएगा और अगले साल उससे ऊपर करना होगा। अगर बोनस दे दो, तो वह हमने आपको गिफ्ट दिया। जब अप्रैल के आखिर में आपने दिया और जब सारी व्हीट व्यापारी ले गए, तो small farmer को कहा कि यार, पांच रुपए और ले लो मिनिमम पर, दस ले लो और उस बेचारे ने ले लिए। तो जो आपका बोनस है, वह तो trader को गया और एक बड़ी अजीब चीज़ हुई पिछले चार दिन में, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 27 करोड़ व्हीट के लिए कहा कि हम बजट से देंगे और वे दे रहे हैं। जो किसान ऐसे धोखे में आ गए, क्योंकि दिल्ली का फैसला ठीक नहीं हुआ, तो हम दे देते हैं। तो यह तो और भी अजीब चीज़ है पंजाब के लिए कि ग्रो भी हम करें, खर्चे भी हम बरदाश्त करें, बिजली भी हम खरीदकर लाएं उड़ीसा से डबल कीमत पर, ट्यूबवैल के लिए, धान के लिए। हम तो धान नहीं खाते हैं। कितना खा लेंगे? साठ परसेंट सरप्लस है देश का और फिर कीमत आप नहीं देंगे और वह भी मैं अपनी जेब से अपने आपको ही दूंगा। मैं किसान भी हूं, मैंने इधर टैक्स दिए और वही टैक्स निकालकर अपने आपको दे दूं? इसको पंजाबी में कहते हैं - "साड्डा ई सिर मुन के सान्नूं दे देओ।" "Chop up my hair and put it in my *jholi*." What sort of economics is this? Can anybody explain to me? Give them reasonable prices; announce them in good time. I have been talking with the Agriculture Minister and I hope that he is going to give us some good answers or some answers worthwhile, and some hope to the farmers, not just of Punjab but of everywhere -- Haryana or U.P. or Bihar or south or north. It doesn't matter. I hope he will give it and the prices even for the next wheat crop will be announced in time after careful consideration. You give for farmer some incentive to grow it; you give him some incentive to give it to your procurement agencies. आपको जरूरत पड़नी है, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल होगी और जो suicides की दिक्कत है, किसानों की, उसके लिए चाहे वह कहीं का भी हो, पंजाब का हो या आंध्र का हो, सबके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा, आप कृपा करके ध्यान दें और मैं आखिर में यह बात जरूर दोहराऊंगा कि बड़े-बड़े economists बैठे हैं, प्रधान मंत्री जी

हैं, जो दुनिया के माने हुए economist हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत जानते हैं, और बहुत से हैं, लेकिन इतना मेरा ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : जयराम रमेश भी हैं।

डा0 एम0 एस0 गिल : हां जी, जयराम रमेश भी बैठे हैं, पर इनका attitude किसानों के बारे में कुछ और रहता है। पर जो भी बैठे हैं, मैं तो कम जानता हूं। उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : पीछे भी एक हैं।

डा0 एम0 एस0 गिल : सर, मैं तो इतना ही नुक्ता आखिर में रखना चाहता हूं कि आज जो देश की overall economic growth की पॉलिसी हो रही है, उसमें बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, आप बड़ा-बड़ा सोच रहे हैं, पर जो मैंने दो सफे Economics के पढ़े हैं, वह यह है कि हिंदुस्तान का जो रूरल भाग है, जो अब भी रूरल है, तीस साल बाद भी मेजॉरिटी जिसकी रूरल ही होगी, उसको साथ लेकर चलना होगा। किसान को भूखा नहीं मारना होगा। उसने आपको रोटी देनी है, तो थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ो, धन्यवाद।

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, इस सदन में अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है। यह सच है कि इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यदि किसी सैक्टर में लगी हुई है तो एग्रीक्लचर सैक्टर में लगी हुई है। सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं यदि किसी क्षेत्र में हैं तो वे एग्रीक्लचर सैक्टर में हैं, लेकिन आज किसानों की हालत कितनी बद से बदतर हो चुकी है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति इससे परिचित है। श्रीमन्, मैं पहले आंकड़ों को आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन कुछ कहने से पहले मैं आपके माध्यम से, माननीय कृषि मंत्री जी से भी यह कहना चाहूंगा कि यदि हम चर्चा प्रारम्भ कर रहे हैं, तो जो हमारा अन्नदाता किसान है, उसकी आत्महत्या पर राजनीति की रोटी सेकना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि किसान किन कारणों से आत्महत्या कर रहा है, उन कारणों को समझा जाए और उनका समाधान किया जाए। महोदय, यह भी विडम्बना है कि इस हिन्दुस्तान में लम्बे समय तक यदि किसी एक पार्टी की हुकूमत रही है तो आज जिस पार्टी की केन्द्र में सरकार है, उसी की हुकूमत रही है। यानी विशेष रूप से एकछत्र हुकूमत यदि किसी की रही है तो वह कांग्रेस की हुकूमत रही है। मैं इस सरकार को स्मरण कराना चाहता हूं कि जो इस देश के प्रथम प्रधान मंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू थे, उन्होंने यह कहा था कि हम अन्य समस्याओं के समाधान में तो कुछ विलम्ब कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन कृषि जगत से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में रंचमात्र भी विलम्ब नहीं कर सकते। उनका कहना था कि यदि हमने कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में विलम्ब किया तो इस देश की अर्थ व्यवस्था चरमरा कर बैठ जाएगी। यह बात पं0 जवाहर लाल नेहरू ने उस समय कही थी, लेकिन आज आजादी के 59 वर्ष गुजर गए हैं और लम्बे समय तक एक ही राजनीतिक पार्टी की हुकूमत इस हिन्दुस्तान में रही है, फिर भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आज किसान यह मानने लगा है कि उसकी खेती अब लाभकारी नहीं रह गई है, अब वह घाटे का सौदा हो गया है। अब वह अपने उस कृषि कार्य से हटने की बात भी सोच रहा है और एक बड़ी संख्या में नेशनल सैम्पल सर्वे का जो सर्वेक्षण आया है, उसमें भी यह बात आई है कि ऐसे बहुत सारे किसान परिवार हैं, जिनको अब यह महसूस होने लगा है कि अब

हमारी कृषि लाभकारी नहीं रह गई है, इसलिए वे कृषि के पेशे से दूर हटना चाहते हैं। इसके साथ ही अब लोग यह भी मानने लगे है कि कृषि का कार्य उतना सम्मान जनक नहीं रह गया है, जितना कि अन्य पेशे में काम करना सम्मानजनक होता है। महोदय, मैं तो यह मानता हूं कि जिस दिन इस देश के किसान का बेटा यह फैसला करेगा कि क्लास फोर की नौकरी नहीं करेंगे, यदि हमारे पास थोड़ी बहुत भी जमीन है तो निश्चित रूप से अपनी खेती के माध्यम से अपनी जीविका चलाएंगे और किसान भी यह महसूस करने लगेगा कि हमारे बाद हमारा बेटा भी किसान होना चाहिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस दिन देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन आज जो ऐसे हालात पैदा हुए हैं, उनके पीछे क्या-क्या कारण हैं, मैं उन कारणों का भी यहां संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। किसान जितना भी इनपुट अपने इस कृषि क्षेत्र में लगाता है, उस हिसाब से उसको उसकी कीमत नहीं मिल पाती है, इस समय सबसे बड़ा संकट यही है। सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइज निर्धारित की जाती है, लेकिन मैं जानता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज इस बात को ध्यान में रखकर निर्धारित नहीं की जाती है कि किसानों के लिए यह खेती का काम कैसे लाभकारी हो जाए। ऐसे बहुत सारे कम्पलशंस होते होंगे, मैं यहां पर उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइज ऐसी दी जाए, ताकि उनकी खेती उनके लिए लाभकारी हो जाए। जो भी किसान कृषि के क्षेत्र में इनपुट्स डालता है, चाहे वह डीज़ल हो, बीज, पेस्टीसाइड्स हों, ये जो सारी चीजे हैं, उनकी कीमतें भी बेतहाशा बढ़ी हुई हैं। इनकी कीमतें बढ़ने के अतिरिक्त, इस गवर्नमेंट के आने के बाद महंगाई भी तेजी के साथ बढ़ी है। जहां तक डीज़ल का सवाल है, पिछले 2 वर्षों में डीज़ल की कीमत 6 से लेकर 7 बार बढ़ी है। आज़ाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा कभी नही हुआ होगा कि दो वर्षों के अंदर डीज़ल की कीमत इतनी तेजी के साथ बढ़ी होगी और यह महंगाई बढ़ने का ही परिणाम है, agricultural inputs के महंगे होने का ही परिणाम है कि किसानो द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं बढ़ी हैं। मैं उन आंकड़ों का भी यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में वर्ष 2004-05 में 1,068 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। यह मैं वर्ष 2006 की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ष 2005 की बात कर रहा हूं, वर्ष 2006 के आंकड़े तो और हैं, और बड़े आंकड़े हैं। मैं देख रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में भी किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, कर्नाटक में भी किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, महाराष्ट्र में भी किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। भले ही मंत्री जी ने यह उत्तर दिया हो कि पंजाब में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन गिल साहब ने बतलाया कि पंजाब में भी किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। केरल में वर्ष 2005 मे 21 किसानों ने आत्महत्या की। मैं देख रहा हूं कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, उन्हीं राज्यो में सर्वाधिक किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह कैसी विडंबना है, क्या कारण है, क्यों नहीं आपकी सरकार वहां के किसानों की समस्या का समाधान निकाल पा रही है?

उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार को सचमुच किसानों के प्रति जितना संवेदनशील होना चाहिए, उतनी संवेदनशील वह नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सहानुभूति और संवेदनशीलता में एक ऐसी कुव्वत होती है, एक ऐसी ताकत होती है कि बड़े से बड़ा करिश्मा इसके माध्यम से किया जा सकता है। मैं उस घटना का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई थी, जहां प्रिंस नामक 4 वर्ष का बालक 60 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था, भले ही वह बालक, वह बेटा अकेला रहा हो, लेकिन सारे देश की दुआएं,

सारे देश की सहानुभूति, सारे देश की संवेदना उस बच्चे के साथ थी और आपने देखा कि वह बच्चा बच निकला। मैं यह मानता हूं कि सचमुच यदि किसानों की समस्या के समाधान के प्रति यह सरकार संवेदनशील हो जाए, तो मैं समझता हूं कि उनकी समस्याओं का समाधान निकालना कठिन नहीं होगा।

उपसभापति महोदय, सरकारी की सारी नीतियां - चाहे वह मूल्य नीति हो, चाहे आयात नीति हो, चाहे वह निर्यात नीति हो - इतनी दोषपूर्ण हैं कि जिनके कारण यह संकट निरंतर गहराता जा रहा है। आज़ादी के इतने वर्ष गुज़र जाने के बावजूद आज हमारे देश की 40 से 42 फीसदी जमीन सिंचित हो पाती है, लेकिन लगभग 58 फीसदी जमीन आज भी असिंचित है। कैसे किसान की खेती उसके लिए लाभकारी होगी, इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपसभापति महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, natural calamities के कारण किसान की पूरी की पूरी फसल बरबाद हो जाती है, फिर किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं रहता है, चिंता करने वाला कोई नहीं रहता है। किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के पीछे, जहां उनके produce की, उनके उत्पाद की उचित कीमत न मिलना एक कारण है, वहीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो उनकी फसल बरबाद हो जाती है, वह भी एक कारण है, जिसके परिणामस्वरूप वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं।

उपसभापति महोदय, WTO के जो provisions हैं, उनका भी मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। WTO के जो provisions हैं, उनमें कृषि जिंसों के इंपोर्ट पर हमारी गवर्नमेंट 100-150-300 परसेंट तक इंपोर्ट टैक्स लगा सकती है, ताकि जो देश सब्सिडी देते हैं, उनके competition में, उनकी स्पर्धा में भारत का किसान भी खड़ा हो सके, लेकिन हो क्या रहा है कि आज OECD नामक 20 अमीर देशों का एक क्लब है और ये 20 अमीर देश, अपने-अपने देशों में खेती को लगभग 44 परसेंट का अनुदान देते हैं और इन देशों ने अपने किसानों को 350 बिलियन डालर की जो सब्सिडी दी है, वह हमारे टोटल नेशनल इनकम का 60 परसेंट बनता है, जबकि WTO में ही इन सारे अमीर देशों ने वादा किया था कि हम 10 वर्षों के अन्दर सब्सिडी को घटा कर 5 परसेंट अथवा इसके निचले स्तर पर लाएंगे, लेकिन किसी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। हालात इस सीमा तक बदतर हो गए हैं कि जापान में पहले 68 परसेंट की जो सब्सिडी होती थी, उसे उसने अब 70 परसेंट कर दिया है, कोरिया में किसानों को 54 परसेंट की जो सब्सिडी दी जाती थी, वह 58 परसेंट हो गई, अमेरिका में ही आज से डेढ़ वर्ष पहले 180 बिलियन डालर एडीशनल सब्सिडी की घोषणा अमेरिकन गवर्नमेंट ने की। और हमारी गवर्नमेंट इम्पोर्ट टैक्स बढ़ाने के बजाय उस इम्पोर्ट टैक्स को कम कर रही है और उसे 50 परसेंट से लेकर 0 परसेंट तक इम्पोर्ट टैक्स, जो हमारे कृषि जिंस हैं, जो हमारे खाद्यान्न हैं, उन पर इस सीमा तक लाकर उसे कम किया है। कैसे हमारे देश का किसान दुनिया के दूसरे देशों के किसानों की स्पर्द्धा में खड़ा हो पाएगा? मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस सरकार ने यह सोच रखा है, मन बना रखा है कि हम इस देश के किसानों की आत्मनिर्भरता पूरी तरह से समाप्त कर देंगे? जो भारत विगत एक दशक से खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर माना जाता था, वह भारत आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर न रह जाए, क्या इस सरकार की यही सोच है? यदि हम ऐसे ही इम्पोर्ट टैक्स घटाते रहे, तो 100, 150, 300 परसेंट टैक्स लगाने का हमारा अधिकार भी हमेशा के लिए

3.00 P.M.

समाप्त हो जाएगा, क्योंकि WTO की provisions ही यही हैं कि यदि आपने 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष तक जितना आपको इम्पोर्ट टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त है, यदि उतना इम्पोर्ट टैक्स आपने नहीं लगाया, तो फिर आपका यह अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0 जे0 कुरियन) पीठासीन हुए]

अब जब ऐसे हालात पैदा होंगे, तब तो स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। अब यह क्या हो रहा है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। मैं एनडीए शासन काल में याद दिलाना चाहता हूँ कि चाहे वह चावल रहा हो, चाहे गेहूँ रहा हो, चाहे दाल रही हो, कई ऐसे फूड आइटम्स थे, कई ऐसे खाद्यान्न थे, जिनका हम बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते थे। आज 2-2.5 वर्षों के अन्दर ही इस प्रकार के बदतर हालात क्यों पैदा हो गए, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से इसका भी उत्तर चाहूँगा।

अभी हाल ही में मार्च के महीने में इस गवर्नमेंट ने फैसला किया - आस्ट्रेलिया से, अमेरिका से गेहूँ इम्पोर्ट करने का। क्या जरूरत थी इस गेहूँ को इम्पोर्ट करने की? मार्च के महीने में मार्केट में किसानों का गेहूँ आ जाता है और उसी मार्च के महीने में यह फैसला किया जा रहा है कि हम दुनिया के दूसरे देशों से गेहूँ इम्पोर्ट करेंगे। हम क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रीमन्, मैं यह भी बतलाना चाहता हूँ कि मुझे इस बात की पक्की जानकारी है कि यह जो गेहूँ की crisis दिखाई गई है, वह एक manufactured crisis है, वह reality नहीं है, वह artificial crisis है। सच्चाई यह है कि हमारे देश में गेहूँ की उतनी कमी नहीं हुई थी। अब हम आस्ट्रेलिया से 9.50 रुपए, 10 रुपए, 10.50 रुपए, 11 रुपए per kg के हिसाब से गेहूँ खरीद रहे हैं और अपने किसानों को हम 8 रुपए per kg के हिसाब से कीमत नहीं दे पा रहे हैं। आज गेहूँ की कीमत 700-750 रुपए per quintal है, 700 रुपए minimum support price निर्धारित हुई थी और उस पर 50 रुपए का बोनस दिया जा रहा है, इस प्रकार 750 रुपए है। मेरा यह कहना है कि यदि आप आस्ट्रेलिया, अमेरिका से 9.50 रुपए, 10 रुपए per kg के हिसाब से गेहूँ इम्पोर्ट कर रहे थे, तो आपने अपने किसानों को 9 रुपए per kg अथवा 10 रुपए per kg के हिसाब से गेहूँ की कीमत क्यों नहीं दी? आपने क्यों नहीं किसानों से इस कीमत पर गेहूँ खरीदी?

श्रीमन्, मैं विदर्भ के एक संकट बारे में भी कहना चाहता हूँ। माननीय कृषि मंत्री जी भी महाराष्ट्र प्रदेश के ही रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट भी है। वहाँ का संकट बहुत बड़ा संकट है। मैं स्वयं विदर्भ के दौरे पर गया था। महोदय, किसानों की आत्म-हत्या की खबरें जब निरंतर बढ़ती हुई जानकारी में आने लगीं तो मैने विदर्भ में क्षेत्र में जाने का फैसला किया और मैं वहां गया। प्रधान मंत्री जी वहां गए थे। उन्होंने वहां पर 3750 करोड़ रुपए के एक रिलीफ पैकेज की भी घोषणा की, लेकिन सारी स्थिति को समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि विदर्भ क्षेत्र में यदि सर्वाधिक आत्म-हत्याएं होती हैं तो वे कॉटन हार्ट लैंड में ही सर्वाधिक होती हैं। महोदय, मैं यहां पर विदर्भ की एक जन आंदोलन समिति के सर्वे का उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा जिस में उस जन आंदोलन समिति ने अपने सर्वे में कहा है कि जून और दिसंबर, 2005 के बीच 212 फार्मर्स ने suicide किया जिस में से 182 कॉटन हार्ट लैंड के हैं और 182 में से 170 किसान मोनसेंटो बी0टी0 कॉटन ग्रोअर्स हैं।

महोदय, यह बी0टी0 कॉटन भी वहां के किसानो को आत्म हत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। मोनसेंटो, जेनेटिकल मॉडीफाइड कॉटन सीड जितनी कीमत में यू0एस0 के फार्मर्स को बेचता है, लगभग उतनी ही कीमत मे वह इंडियन फार्मर्स को भी बेचता है। उस की कीमत अब द 1600 रुपए प्रति 450 ग्राम है। श्रीमन्, आप को आश्चर्य होगा इस में रॉयल्टी कम्पोनेंट 1200 रुपए का है और बी0टी0 कॉटन के ये गुण बताए जाते हैं कि बी0टी0 कॉटन का प्रयोग करने से कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन विदर्भ में क्या हालत है, इस का अनुमान विदर्भ में जाकर ही लगाया जा सकता है। महोदय, मैं बी0टी0 कॉटन के बारे में कहना चाहता हूं कि BT Cotton has emerged as a killer for the farmers of Vidharbha, Andhra Pradesh, and Karnataka also.

अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बी0टी0 कॉटन के कारण पैदा संकट को समझा है और समझने के बाद उन्होंने मोनोपोली एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन के सामने एक केस फाइल किया है, लेकिन अब तक उस की क्या प्रगति है, इस् संबंध मे मुझे जानकारी नहीं है। शायद हमारे कृषि मंत्री जी उस के संबंध में हमे बतला सकेंगे।

महोदय, एक संकट जो सीड्स के बारे में पैदा हो रहा है, उस की भी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। महोदय, इस समय 10 मल्टीनेशनल कंपनीज भारत के अंदर सीड्स बेचने का काम कर रही हैं। हमारे यहां का किसान अपने ट्रेडीशनल सीड्स के आधार पर इस देश में उत्पादन करता रहा है, उत्पादन बढ़ाता रहा है और हमारे किसान के समक्ष कभी कोई ऐसा संकट पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जो सीड्स ग्लोबल कंपनीज के द्वारा बेचा जा रहा है, उस के कारण भी हमारे किसानों के समक्ष एक संकट पैदा हो रहा है। इस कारण बीज महंगे हो रहे हैं, महंगे रेट पर उस बीज को खरीदने के लिए किसान मजबूर है, लेकिन जिस रेट से वह बीज खरीदता है, उस रेशियो मे उस की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, उस का उत्पादन नहीं बढ़ता है और स्वाभाविक रूप से आज उस का यह कृषि कार्य घाटे का सौदा बन जाता है।

महोदय, मेरी जानकारी में एक बात आई है कि U.S. India Knowledge Initiative in Agriculture नामक एक योजना आरंभ की गयी है। मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह योजना क्या है? क्या यह योजना भी उसी तरह एक किलर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करेगी? महोदय, यह योजना एक ग्लोबल कंपनी Wallmart & Monsanto द्वारा चलायी जा रही है। श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या ये ग्लोबल कंपनीज हमारी फूड सेक्युरिटी की गारंटी दे पाएंगी? क्या ये फार्मर्स की जीविका की, उन की livelihood की चिंता कर पाएंगी? मैं समझता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन कंपनीज के द्वारा यह चिंता नहीं की जा सकती है।

सर, अब मैं यहाँ पर इस समस्या के समाधान के सम्बन्ध में थोड़ी-बहुत चर्चा करना चाहूँगा। किसानों की जो भी असिंचित भूमि है, यदि उस किसान ने कोई लोन लिया है, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, वह पूरी तरह से माफ किया जाना चाहिए। कम-से-कम जो असिंचित कृषि क्षेत्र है, उस पर से माफ किया जाना चाहिए। किसानों को जो लोन दिया जाता है, उस पर कमर्शियल बैंक्स का रेट ऑफ् इंटरेस्ट आज 9 फीसदी या साढ़े आठ फीसदी है। एग्रिकल्चरल क्रेडिट पर यह रेट ऑफ् इंटरेस्ट है। जहाँ तक प्राइवेट मनी

लेंडर्स हैं, वे तो आजकल 50 परसेंट से लेकर 100 परसेंट के रेट ऑफ् इंटरेस्ट पर किसानों को यह कर्ज दे रहे हैं।

मैं समझता हूँ कि यह कर्ज एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते वह किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। वह स्वाभिमान की जिन्दगी जीना चाहता है, लेकिन यह सरकार इस देश के किसान को स्वाभिमान की जिन्दगी भी जीने नहीं दे रही है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों को एग्रिकल्चरल काम के लिए, कृषि कार्य के लिए जो लोन दिया जाए, उस पर रेट ऑफ् इंटरेस्ट किसी भी सूरत में 4 परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो लोन दिया जाए, उस लोन के ऊपर, उस क्रेडिट के ऊपर, कम-से-कम दो साल के लिए किसी भी प्रकार का कोई रेट ऑफ् इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, ब्याज नहीं लगना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे कृषि मंत्री जी और साथ ही हमारे वित्त मंत्री जी भी, जो इस समय यहाँ नही हैं, इस पर भी विचार करेंगे।

श्रीमन्, मैंने प्राकृतिक आपदा की चर्चा की थी ...**(व्यवधान)**... उन्हें रहना तो चाहिए, लेकिन वे नही हैं ...**(व्यवधान)**...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, last time, when the discussion took place, we made an appeal to the House that this is a very important subject and this cannot be dealt alone by the Agriculture Minister because most of the policy-related issues are with the Finance Ministry. It was suggested at that time. We thought that the Finance Minister will also be here during this important discussion.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Last time, he was here, but Sharad*ji* was not here.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: He had just come and gone. I don't know if he can be called by the Parliamentary Affairs Minister. We are not making a complaint. But, for a better and a constructive discussion, it will be useful for the House.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That's okay, but the Agriculture Minister is here.

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): वित्त मंत्री जी का रहना बहुत आवश्यक है। ऐसे संवेदनशील विषय पर इतनी असंवेदनशीलता ठीक नही है, उपसभाध्यक्ष महोदय। ...**(व्यवधान)**... वित्त मंत्री जी को उपस्थित रहना चाहिए ...**(व्यवधान)**...

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक विवरण मंत्री (श्री शरद पवार): वे रहते हैं, तो उनको रहने नहीं देते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : क्योंकि वे आपको पैसा देगे। जैसे 15 सौ करोड़ रुपए विदर्भ को दिया, आन्ध्र को भी दिया। उत्तर प्रदेश में भी सूखा पड़ जाए, तो हमें भी मिल जाए ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It is not necessary that the Minister should be here to be aware of the discussion that is taking place. The Agriculture Minister is competent enough to deal with this. But, the Finance Minister will certainly get all the information from here. If he comes, it would be better. However, even if he is not here.....

श्री राजनाथ सिंह : श्रीमन्, मैं एग्रिकल्चरल लोन के बारे में यह कहना चाहूँगा कि मैंने यह माँग की कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी सूरत में 4 परसेंट से अधिक नही होना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद चीन में किसानों को जो लोन दिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। वह कितने वर्षों के लिए नहीं लगता है, यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में जो बात है कि शायद चीन में इस प्रकार से कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। एग्रिकल्चर सेक्टर में यदि कोई देश सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो चीन करता है। हम उसके पड़ोसी देश हैं। अब एग्रिकल्चर सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का है? First Five Year Plan, Second Five Year Plan और Third Five Year Plan में एग्रिकल्चर सेक्टर में हमारा जितना इन्वेस्टमेंट था, मैं समझ रहा हूँ कि हमारा वह इन्वेस्टमेंट निरन्तर घटता ही जा रहा है। यह एक चिन्ता का विषय है। मैं यह मानता हूँ कि यदि हम कृषि के क्षेत्र को लाभकारी बनाना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ इसे भी मैं स्वीकार करता हूँ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन, जब मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सारी ग्लोबल कम्पनीज़ आकर यहाँ पर उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करें, बल्कि किसानों की परचेजिंग कैपेसिटी, उनकी आमदनी इतनी बढ़ाई जाए, ताकि उनके अन्दर अपने कृषि कार्य में अधिक-से-अधिक इन्वेस्ट करने की क्षमता पैदा हो सके। यह आवश्यक है।

श्रीमन्, मैंने एम0एस0पी0 के बारे में भी चर्चा की। एम0एस0पी0, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में एक बार माननीय कृषि मंत्री जी विचार करें और इस बात को ध्यान में रख कर विचार करें, ताकि किसानों के लिए यह खेती का कार्य उनके लिए लाभकारी हो सके। उपसभाध्यक्ष जी, मैं यहां पर कोआपरेटिव्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। कई ऐसे राज्य हैं, जहां पर कोआपरेटिव बैंक्स और कोआपरेटिव सोसायटीज की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वित्त मंत्री जो ने जो अपनी पहली बजट-स्पीच दी थी, मुझे स्मरण है, उन्होंने कहा था कि जिन कोआपरेटिव बैंक्स की अथवा कोआपरेटिव सोसायटीज की हालत बिगड़ चुकी है, हम उन सारे कोआपरेटिव बैंक्स और कोआपरेटिव सोसायटीज के हालात में सुधार लाएंगे। यह बात हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा किसान यदि लोन लेता है, तो 70 परसेंट किसान कोआपरेटिव बैंक्स के माध्यम से ही लेता है और जहां तक कॉमर्शियल बैंक्स का सवाल है, कॉमर्शिल बैंक्स से तो केवल 20 परसेंट ही हमारा किसान लोन लेता है। मैं जानना चाहूंगा कि इन कोआपरेटिव बैंक्स, कोआपरेटिव सोसायटीज की हालत सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? और, इस आग्रह के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि अब तक आपने कोई कदम नहीं उठाया है, तो निश्चित रूप से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाना चाहिए। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मल्टीस्टेट्स कोआपरेटिव एक्ट के बारे में अब तक क्या हुआ है? इसकी प्रगति क्या है? कितने राज्यों ने इसे स्वीकार किया है? मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी हमारे कृषि मंत्री जी जब अपना उत्तर देंगे, तो जरूर देंगे।

श्रीमन्, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में कृषि-योग्य 40 फीसदी भूमि ऐसी है, जो सिंचित है और लगभग 58-60फीसदी असिंचित है। बड़ी-बड़ी सिंचाई की परियोजनाओं के माध्यम से सारी कृषि योग्य भूमि को सिंचित नहीं बनाया जा सकता, बल्कि मैं यह मानता हूँ कि छोटी परियोजनाओं के माध्यम से ही अधिक से अधिक कृषि-योग्य भूमि को सिंचित बनाया जा सकता है और इसलिए छोटी सिंचाई परियोजनाओं को सरकार की तरफ से कैसे अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, इसकी भी शासन को चिंता करनी चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि हमारे देश में मार्जिनल फार्मर्स 22.3 परसेंट हैं और जिनको लेंडलेस फार्मर्स कहते हैं उनका परसेंटेज 40.9 है। सरकार से मैं यह अपेक्षा करुंगा कि सरकार इनके लिए ऐसी मार्केट कमेटीज बनाए, जो इनके अनुकूल हों। अब सारे के सारे सीमांत किसानों के माल को, इनके उत्पाद को, मैं समझता हूँ, कैपिटल मार्केट के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा इस पर भी चिंता करना आवश्यक है।

श्रीमन्, लोन के बारे में एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करुंगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0 जे0 कुरियन) : लोन के बारे में तो आप बोल चुके हैं। ...**(व्यवधान)**... Don't go back to the points because there is a constraint of time.

श्री राजनाथ सिंह : सर, मैं बोल चुका हूँ, लेकिन इसमें एक बात रह गई थी, उसकी भी चर्चा कर देना चाहता हूँ। जो किसानों के ऊपर कर्ज है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां पर स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, वहां पर उनके इस लोन की, इस क्रेडिट की वन टाइम सेटलमेंट करने पर भी विचार करना चाहिए, केवल कभी-कभी टोकन रिलीफ पैकेज देने से किसानों का कोई कल्याण नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, इस समय इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतनी ही सरकार से अपेक्षा करुंगा कि यह सरकार किसानों की भूमिका के साथ न्याय करे, क्योंकि किसान इस देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसान इस देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ग्राहक है। जिस दिन किसान की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिस दिन किसान की क्रय-क्षमता हो जाएगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई हासिल करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, असल में यह विषय बहुत ही उदास है और अगर मैं ज्यादती न करुं, तो मैं कहूंगा कि यह बहुत ही मनहूस विषय है, जिस विषय पर हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं। वे लोग कितने मरे हैं, जो हमारी रोटी का इंतजाम किया करते हैं, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत उदास, मैंने जानबूझ कर कहा। कभी-कभी हम लोग अपने गांव में होते हैं, कोई मर जाता है, मिट्टी होती है, उसी समय कोई खुशी की खबर आती है कि गांव का लड़का जिला की फुटबाल टीम में चुन लिया गया है, तो थोड़ी देर के लिए उदासी खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह से खेती के इस मुद्दे पर जब हम बहस करते हैं तो अखबारों में छपता है कि हिन्दुस्तान की खेती का मिनिस्टर हिन्दुस्तान की खेल कम्पनी का बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा मालिक है, चुनाव जीत गया है, तो थोड़ी देर के लिए उदासी कम हो जाती है। लेकिन, खेती खेल नहीं है। मंत्री महोदय, मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी देश का खेती-बाड़ी का मंत्री खेल में दिलचस्पी

नहीं रखता, क्योंकि खेती 24 घंटे का काम है। कितना समय आप देते हैं क्रिकेट में और कितना समय देते हैं खेती में, कभी इसका हिसाब-किताब होगा। संसद आपसे पूछ नहीं पाएगी, क्योंकि यह आपका व्यक्तिगत मामला कहा जाएगा। लेकिन, यह बहुत गंभीर मामला है और जब कभी हिन्दुस्तान की खेती खेल बन जाएगी, उस दिन हिन्दुस्तान का किसान खुदकुशी करने लगेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। परिस्थितियां इस तरह से बन जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत उदास और बहुत मनहूस विषय पर डा0 एम0एस0 गिल और श्री राजनाथ सिंह जी ने चर्चा उठाई है।

अभी-अभी प्रधानमंत्री जी विदर्भ गए, उस इलाके में गांधी जी का एक आश्रम भी है, वर्धा गए ही होंगे, क्योकि आम तौर पर रस्म के तौर पर प्रधानमंत्री, मंत्री या नेता लोग जब वहां जाते हैं तो वर्धा दर्शन करने जाते हैं। पता नहीं गांधी जी के उस वर्धा आश्रम से उनको कितनी प्रेरणा मिली होगी या हम लोगों को कितनी मिलती है, लेकिन खेती के बारे में तो गांधी जी की अपनी एक दृष्टि थी। घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पाद के बारे में तो गांधी जी की अपनी एक दृष्टि थी। हम यह नहीं कहते कि जिस बेतहाशा दौड़ में दुनिया के साथ हम जाना चाहते हैं, उद्योग जगत में न जाएं, लेकिन अपना घर संभाल कर जाना चाहिए। आज लगता है कि हमारा घर उजड़ सा रहा है। हमने यह जो आत्महत्या की रिपोर्ट देखी है, जिसको राजनाथ सिंह जी पढ़कर सुना रहे थे कि इतनी आत्महत्याएं कब हुईं, कब हुईं, ये सब जितनी आत्महत्याएं हुई हैं, केवल मर्द लोगों की हुई हैं। हमारी बहनें कभी-कभी 33 परसैंट रिज़र्वेशन का हक मांगती हैं, इन आत्महत्याओं में कहीं 33 परसैंट इनका है ही नहीं। ...**(व्यवधान)**... महिलाएं आत्महत्या नहीं करतीं और महिलाएं ही नहीं, खेती में जो मजदूरी करता है, वह तो महिलाओं से भी ज्यादा बद्तर हालात में होता है किसान के घर में, वह आत्महत्या नहीं करता, वह भुखमरी का शिकार हो जाता है, मंत्री जी, जिसकी चर्चा ही हम लोग नही कर रहे हैं। गरीब किसान जब खुदकुशी करता है तो जिस हालत में, उसकी जो माली हालत होती है, उसके बच्चे और घर की महिलाएं भुखमरी का शिकार होती हैं, उसके खेत में जो मजदूरी करता है, वह मजदूर भुखमरी का शिकार होता है, वह आत्महत्या का शिकार नही होता। यह टोटल आप जोड़ेंगे तो बड़ी भयानक तस्वीर हिन्दुस्तान के खेत की जमीन पर इस समय बनी हुई है, जिस पर हमको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्या वाकई इसी तरह से चलता रहेगा?

यह सही है कि हिन्दुस्तान की ज्यादातर खेती आसमान पर मुनहसिर करती है। पानी बरस जाएगा, तभी खेती अच्छी होगी। जमीन से पानी निकालने का या जमीन पर जो पानी बहता है, उस पानी का इस्तेमाल करने का कोई रास्ता हम लोगों ने बहुत कम निकाला है। आजकल बरसात का मौसम है, लेकिन कई इलाकों में पानी ही नहीं बरस रहा है, सूखा है, किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है और कई जगहों पर तो, देहातों में जाने पर यह रिपोर्ट मिलती है कि पानी बरस जाए समय से, इसके लिए गांव में किसी नाई की औरत या कोई औरत कपड़े उतारकर रात में हल चलाती है ताकि इंद्र भगवान खुश हो जाएं। हिन्दुस्तान सीता-सावित्री का देश है, द्रौपदी का देश है, जहां सीता-सावित्री की बेटियां खुदा को खुश करने के लिए, ताकि उसके खेत में हरियाली आ जाए, अपने कपड़े उतार दें और यह सरकार यहां पर बैठकर बोले कि हम मंत्रालय चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है। खेती खेल में नहीं गुजरनी चाहिए, मैं इतना निवेदन करुंगा, यह मेरा पहला वाक्य है। बहुत भयानक तस्वीर है, ऐसी तस्वीर है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती और इस तस्वीर को बनाती है सरकार

की नीतियां। कभी भी खेती की इस दुर्दशा के बारे में कोई गोष्ठी ही नहीं होती है। खेती के बारे में तो गोष्ठी या विचार बैठक होती है, क्योंकि वह खेती बड़े घराने के लिए हुआ करती है, वह टेक्निकल खेती होती है, लेकिन आम तौर से जो हमारे यहां खेती हुआ करती है, उसके बारे मे कभी कोई चर्चा नहीं हुआ करती है और सर, जब चर्चा नहीं होती है तो जो दर्द उभरता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

हमारा देश गरीब देश है। हम केवल दिल्ली और मुम्बई को दिखा कर कह देते हैं कि हम विकासशील देश हो रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब हम अपने गांवो को देखते हैं तो हम अभी विकास की तरफ जा भी रहे हैं या नहीं, कहा नही जा सकता। हमारा देश बहुत गरीब है, क्योंकि महोदय, हिन्दुस्तान के उत्पादक श्रम दो ही होते हैं। एक उत्पादक श्रम वह होता है, जो मशीन पर पसीना बहाया करता है और एक उत्पादक श्रम वह होता है, जो जमीन पर पसीना बहाया करता है। हम लोग उत्पादक श्रम वाले लोग नहीं हैं अथवा जो उस गैलरी में बैठते हैं, वे भी उत्पादक श्रम वाले नहीं हैं। हम लोग इंतजामकार हो सकते हैं, लेकिन उत्पादक श्रम तो वही कहलाता है कि अगर जमीन पर या मशीन पर पसीना गिर जाए तो उससे कोई दूसरी चीज़ पैदा हो जाए।

मज़दूर थोड़े-बहुत संगठित होते हैं, जब उनके पसीने का ठीक दाम नहीं मिलता तो कभी-कभी हल्ला बोलते हैं, लेकिन किसान संगठित नहीं होता है, जब वह अपना पसीना जमीन पर गिराता है तो दो मिनट में ही सूख जाता है। मशीन वाला पसीना तो थोड़ा बहुत दिखाई भी देता है इसलिए वह संगठित हो जाता है, लेकिन किसान का पसीना जमीन पर गिरते ही दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि वह बेचारा संगठित नहीं होता, यदि ऐसा होता और अगर वह अपनी जमीन पर बहे हुए पसीने की कीमत लेने चल देता तो खेती और खेल साथ-साथ नहीं चल सकते थे। तब किसान, जो अपने बगीचे में गुलाब लगाता है, उसकी कली किसी नेता, सेठ या अफसर के कोट के गले या जेब में नहीं लगी होती, बल्कि किसान के साफे में लगी होती, लेकिन वह अपना पसीना देख ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वह तो जमीन में गिरते ही सूख जाया करता है और वह उस सूखे हुए पसीने की कीमत न तो सरकार से मांग सकता है और न ही समाज से मांग सकता है। वह अपना पसीना बहाता जाता है, उसकी आह निकलती जाती है, लेकिन और कितनी आह निकालेगा वह? कितना दया का पात्र बनेगा?

हिन्दुस्तान का किसान आज आत्महत्या कर रहा है, क्या आप जानते हैं कि किसान क्या होता है? वह एक गाय जैसा होता है। जब बीजेपी के मित्रों की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में किसी किसान की हत्या हो गई थी, तब एक बार हमने कहा था कि किसान तो गाय होता है और हमने कहा कि तुमने तो गौ-हत्या कर दी। सर, जो गाय होती है, वह अपने थनों में थोड़ा सा दूध अपने बच्चे के लिए बचा करके रख लेती है और बाकी दूसरों को दे दिया करती है। किसान भी थोड़ा सा अनाज अपने बच्चों के लिए बचा लेने के बाद पैदा किए गए बाकी सारे अनाज को दूसरों को खिला देता है। हम पार्लियामेंट के मैम्बर खेती नहीं करते हैं, गेहूं पैदा नहीं करते हैं, यह जो बड़े-बड़े दफ्तर खुले हुए हैं, इनके अफसर और बाबू भी खेती नही करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों की कमाई की आई हुई रोटी यहां पर खाई जाती है। वह गाय जैसा होता है, वह केवल बर्दाश्त करता है, वह तो अपने सींगों को हिलाना भी नहीं जानता, लेकिन यह सब किस सीमा तक होना चाहिए।

अभी हमारे एक मित्र ने कहा था कि इनकी संख्या 65 करोड़ है, अगर कभी करवट बदल देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हम यह तो नहीं कहते कि इनको बगावत के रास्ते पर ले कर जाया जाए, लेकिन उनको इन्सान की तरह रहने के लिए तो छोड़ा जाए। यह जो पैदा करते हैं, उन्हें उसका दाम ही नहीं मिलता है। मंत्री जी, यह जो आपका कृषि मूल्य आयोग बैठता है, ठंडे-गर्म कमरे में बैठ करके उनका भाव तय किया करता है, वह जानता ही नहीं है कि खलिहान में कितनी लू चलती है, वह जानता ही नहीं है कि गेहूं के खेत में कितनी औंस पड़ती है, वह तो बैठ कर केवल भाव तय करता है। जब कारखाने का आदमी अपने लोहे का भाव तय करता है तो जितना इन्पुट लगा रहता है, उपादान लगा रहता है, सबकी कीमत जोड़ता है, उसके साथ ही साथ कारखाने का मालिक अपनी तनख्वाह, अपना शेयर जोड़ता है, मजदूर की मजदूरी जोड़ता है, मशीन का रगड़-घिसाव जोड़ता है और तब जा कर उत्पाद की कीमत तय करता है। किसान के गेहूं की कीमत तय होती है, धान की कीमत तय होती है। तो जिस खेत में किसान अपना धान और गेहूं पैदा करता है उसके साल भर की मजदूरी हम न्यूनतम मजदूरी नहीं कहते, मालिक लोगों की तरह से एक हैसियत की मजदूरी, उसके बाल-बच्चे जो काम करते रहते हैं उसकी हैसियत से उनकी मजदूरी, क्या जोड़ करके भाव तय होता है? और नहीं होता है तो कारखाने की चीज...**(समय की घंटी)**...

दो मिनट में खत्म करुंगा, सर। कारखाने की चीज और खेत-खलिहान की चीज के भाव एक दूसरे को लूटते रहेंगे। पहली मर्तबा ज़ब मैं पार्लियामेंट का मेंबर होकर आया था, सिक्सटीज का जमाना था, इन्दिरा जी प्रधान मंत्री थीं। उपसभाध्यक्ष महोदय, तो हम लोग कभी-कभी नारा लगाते थे कि -"बड़ा निकम्मा शासन है, सवा सेर का राशन है। सड़क पर जुलूस निकालते थे संसो पार्टी, तब हमारे नेता लोहिया जी, राजनारायण जी वगैरह नेता सब हुआ करते थे तब यह नारा लगाते थे। सवा सेर का राशन यानी एक रुपए का एक सेर गेहूं। उस समय किलो नहीं था, और उन दिनों जब मैं फूलपुर चुनाव लड़ने जाता था तो देहात के किसी पैट्रोल पम्प पर जब पैट्रोल भरवाते थे तो पांच रुपए में एक गैलन पैट्रोल मिलता था। पांच लीटर मे एक गैलन होता है। पांच रुपए में एक गैलन पैट्रोल यानी एक लीटर पैट्रोल एक रुपए का एक किलो गेहूं एक रुपए का। आज गेहूं है आठ रुपए किलो और पैट्रोल है पचास रुपए किलो यानी पचास रुपए लीटर। हमारा दाम आठ गुना बढ़ा, हम यह नहीं कहते कि हमारा दाम बढ़ा नहीं है, कल के मुकाबले बढ़ा है। लेकिन हमारे पड़ौस के मुकाबले में नहीं बढ़ा है, तो हम दरिद्र रह गए। दरिद्रता दो तरह की होती है। पहले जो हम कमाते थे उससे ज्यादा कमाएंगे तो कहा जाएगा कि हम थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन हमारा पड़ौसी उससे बहुत ज्यादा कमा गया तो कहा जाएगा कि हम समाज में दरिद्र हो गए। जो पैट्रोल पैदा करेगा, जो पैट्रोल बेचेगा वह पचास रुपए लीटर बेचेगा जो एक रुपए लीटर बेचा करता था। उन दिनों जब हम पहली बार पार्लियामेंट में आए थे और जो गेहूं एक रुपए किलो बेचा करता था उन दिनों वह अब आठ रुपए किलो बेचेगा। यह अर्थशास्त्र समझना पड़ेगा। कहीं न कहीं कारखाने की चीजों के बारे में और किसानी खलिहान की पैदावार के बारे में दाम में सरकार को एक संतुलित नीति बनानी पड़ेगी, वरना यह किसान टूट जाएगा, खुदकशी करता रह जाएगा। इसको रोकना पड़ेगा।

दूसरी बात है - भूमि सुधार कानून। आजादी की लौ में गांधी जी ने इस लहर को जगाया था कि अगर अंग्रेज यहां से चला जाएगा तो जमींदारी खत्म कर दी जाएगी। कुछ सूबों में भूमि सुधार कानून लागू हुआ तथा कुछ सरकारों ने चलाया भी था।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your two minutes are over. ...(*Interruptions*)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, he is giving concrete suggestions.

श्री जनेश्वर मिश्र : बस अब खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन बहुत से सूबे चालबाजी में रह गए, उपसभाध्यक्ष महोदय। एक ही जमींदार सौ एकड़, हजार एकड़, पांच सौ हजार एकड़ जमीन अपने बैल के नाम, अपने कुत्ते के नाम, अपने नौकर के नाम, अपने रसोइया के नाम उसे लिखवा दिया और जमीन का मालिक का मालिक बना रह गया। तो कुछ सूबों में ठीक से लागू हुआ, कुछ में नहीं हुआ। आज भी किसान जहां खुदकशी कर रहा है -महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल वगैरह ये सब हैं। आन्ध्र में भूमि सुधार कानून के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि एक एकड़ जमीन लेने के लिए लगान पर उपसभाध्यक्ष महोदय, या एक बीघा जमीन लेने के लिए उसे बीस हजार, पच्चीस हजार रुपया देना पड़ता है। दूसरी तरफ भूमि सुधार, अब कानून की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इस बीच में खेती के बारे में स्वावलम्बी देश बन सके, हमने जमीन से पैदा करने की बहुत कोशिश की है। तमाम पेस्टीसाइड्स, इनसेक्टिसाइड्स और तमाम फर्टिलाइजर डालकर के आज जमीन की नीचे की जो उर्वरा शक्ति है उसका हमने शोषण किया है। अब कोई भी खेती यदि उसमें तेज फर्टिलाइजर नहीं डाला जाएगा तो पैदावार नहीं दे सकती। किसान की भूख यदि वह कैश क्रॉप पैदा करे, कैश क्रॉप के बारे में आप जानते हैं कि हाई ब्रिड होता है कपास का, वह जितने पानी की जरूरत पड़ती है मामूली बीज के लिए, उससे तीन गुना पानी की जरूरत पड़ती है। पंजाब में तो वह चल सकता है, लेकिन आपके महाराष्ट्र, विदर्भ और कर्णाटक में नहीं चलेगा। इन मजबूरियों को समझना पड़ेगा। आपने विदेश से तो बीज मंगाया, ...**(समय की घंटी)**... किसानों की एक एकाधिकार कमोडिटी संस्था थी और वह भाव तय किया करती थी, उसको आज से दस साल पहले सरकार ने समाप्त कर दिया । ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0 जे0 कुरियन) : मिश्र जी, आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : जो किसान की फली 70 रुपये, 80 रुपये किलो बिका करती थी, वह किसान की फली अब 17 रुपये किलो बिक रही है। अब खेती की ऐसी हालत हो गई है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि इस पर बहस हो सकती है, भले ही डिबेटिंग बहस हो जाए और आप हमसे बार-बार कहते रहें कि तुम्हारे दो मिनट खत्म हो गये, चार मिनट खत्म हो गये, लेकिन हमारे दो मिनट, चार मिनट के भाषण से किसान जो तबाही के आलम पर खड़ा खुदकुशी कर रहा है, वह खुदकुशी भी चोरी से कर रहा है। सरकार ने कानून बनाया है कि जो कोई खुदकुशी करते हुए पकड़ा जायेगा, उसको 1500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा यानी मर गया तो जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन अगर मर गया और उसके बच्चों ने रिपोर्ट नहीं की, तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा। खुदकुशी की बहुत सी रिपोर्ट्स पुलिस थानों में लिखी नहीं जाती हैं, उसको चुपके से दफना दिया जाता है, उसकी तेरहवीं भी नहीं हुआ करती है। जब लोग आंकड़ों की

बात करते हैं कि राज्य सरकारें आंकड़े देती हैं, तब आप उस 1500 रुपये के जुर्माने को भी याद करें कि वहे मरें भी खाने के बिना और मरने पर उन पर जुर्माना हो, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है?

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0 जे0 कुरियन) : आप समाप्त कीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : हम चाहेंगे कि जो भी लोग हों, चाहे वह बीच के सूदखोर हों, चाहे बैंक हो, जिस किसी इलाके में दस-पांच किसान खुदकुशी के शिकार हो जाएं, तो बैंकों और प्राईवेट सूदखोरों का जो कुछ भी पैसा है, उसको सरकार अपने खजाने से जमा करे। किसान का सारे का सारा कर्जा माफ होना चाहिए। मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था पर लोग बहस करेंगे। एक बार चौधरी देवी लाल ने हरियाणा में किसानों का 10 हजार रुपये का कर्जा माफ किया था। यहां पर वित्त मंत्री जी नहीं हैं, बैंकिग सिस्टम से लेकर के, सब लोगों ने कहा था कि खजाना कहां से आयेगा? ऐसा लगता है कि खजाना दिल्ली, मुम्बई में बसे हुए लोगों का ही दिया हुआ है, गांव के किसानों की कमाई से खजाना नहीं भर रहा है। ये लोग जब दफ्तरों में बैठकर खजाने पर बहस करते हैं, तो हमको बहुत हंसी आती है। ...**(समय की घंटी)**... इस खजाने में हमारा दिया हुआ पैसा है। हमारे गांव का जो पैसा बैंकों में जमा होता है, वह केवल हमारे गांव में खर्च कर दो, हम अपने गांवों में सिंचाई और खेती का इंतजाम कर लेंगे। बैंकिंग के बारे में नये सिरे से सोचना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष जी, आपने घंटी तेज़ बजा दी है, इसलिए मैं आपका सम्मान करते हुए अपनी बात बीच में ही खत्म करता हूं। धन्यवाद।

श्री अमर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के विषय पर डिसकशन हो रहा है। यहां पर कुछ बड़े मंत्री उपस्थित हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह हमारे दोस्त हैं, वह सो रहे हैं, आप उनसे कहिए कि कम से कम वह जागे रहें।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Members, there are more than 20 Members who would like to speak. Only three have spoken as of now. It would be nice if those who want to speak cooperate with the Chair. Since this is an important subject, all those who want to speak should be allowed to speak. Therefore, firstly, those points which have already been stated should not be repeated. Please try to stick to the time-limit.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. We are discussing a very serious issue relating to the suicide by farmers in our country. In this august House, we have been discussing this matter continuously. In the last Session, there was a discussion; before that there was a discussion; and, again, this time, we are discussing this issue. After all the discussions, there is some assurance by the Government and it is not fulfilled and the situation gets aggravated throughout the country. This is what has happened.

Sir, nearly one lakh peasants tried to commit suicide in different parts of the country in the last ten years. Whenever you announced a

package, the number of suicides increased. It was reported in the newspapers that when a package was being announced, a peasant was watching the television and he committed suicide because according to the criteria which was announced in the particular package was not helping the farmers but he was very much sure that this package would help him. So, he decided to commit suicide. That is what happened in this country. Sir, this is what is happening every day. There is a reason for this. Unfortunately, the Government is not at all serious about the situation which is prevailing in the villages at the grassroot level in this country. Sir, what is the main reason for suicides? The agriculture is not at all a profitable enterprise in our country even though it is providing livelihood to 62 per cent of the Indian people. So, the policy makers who are thinking about this policy must be very much careful about this factor. You have to provide livelihood to 62 per cent of the population of this country. Unfortunately, the previous Government or this Government is not at all careful about the situation. Sir, the investment in agriculture has come down from 14.9 per cent in the First Five Year Plan to only 5.2 per cent during the Tenth Plan. With regard to the GDP ratio for agriculture investment, if you see and go through the figures for the last seven years, it has come down from 1.6 per cent of the GDP to 1.3 per cent of the GDP in those seven years. This is the situation. Investment is coming down and what is the result of this fall in the investment? The farmers have to invest for themselves more and more. The public investment is coming down. The Government is not investing. So, the farmer is forced to invest. What is the situation, which is prevailing in this country? Sir, you see now the expenditure on agriculture, rural development, irrigation, flood control, village industry, etc. has come down. At the same time, there has been a considerable increase in the prices of important farm inputs during the last five years. For example, during 1990-91 to 1995-96, the average Wholesale Price Index increased by 58 per cent. The total agricultural inputs cost, for fertiliser it increased more by 113 per cent, for irrigation 62 per cent, for diesel 75 per cent than the level of 1991. So, Sir, the cost of inputs for the farmers is increasing day by day. But there is a fall in the prices of agricultural products. The prices are coming down. What is the situation? You are telling our poor farmers to go and compete with the international farmers. With regard to the total subsidy throughout the world, I would submit that it is 300 billion dollars and in which 250 billion dollars have been spent in 21 developed countries. But this poor nation, whatever they are spending, it is only one-sixth of the total subsidy. In this country, you are reducing subsidy. What will happen is

that, naturally, foreign countries and persons from other countries and especially the multinational companies, which are doing agricultural activity, are getting a chance of dumping their products in this country. What happened to cotton from Maharashtra? With regard to cotton, if you think of a farmer from the US, the subsidy and the access to international supply at lower prices is also because of the direct and indirect subsidy, leading to dumping for the US. During the period from 1998 to 2003 the cotton prices in the US were lower than the cost of production, by more than 50 per cent on average. That is the situation. It is very much possible for them to come here and dump it here. What is the situation in this country? Here since the removal of the Quantitative Restrictions huge import of cotton came to this country because of more subsidies in that country. The cotton is coming to this country. Naturally, subsidies have gone down in our country and the prices have gone down from the Minimum Support Price of Rs.2000 to Rs.1800. That is what has happened in this country. This is the situation of our cotton farmers. The cost of pesticides has increased, the cost of inputs has increased, and cost of every thing has increased. The prices have come down. Naturally, they are forced to go and commit suicide and the Government is a mere watchman. The Minister is the Cricket Board President, only a night watchman in agriculture. What is the situation? ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Why are you supporting the Government? ...(*Interruptions*)... You are also responsible. ...(*Interruptions*)... There is a vicarious liability. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Don't yield. Don't yield.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to submit on the serious gravity of the situation. What has happened in this august House? The hon. Finance Minister was forced to admit the situation, when he addressed in this august House, when we had discussion with regard to the prices. I quote Sir, "This a larger question. This must be debated thoroughly. Just take rice. I did not go back very far. Let me go back to only 1993-94. In 1993-94, in the case of Kharif crop, 80 million tons was the total rice production. It remained more or less at the same level for about seven or eight years and went up to 89 million tons in 1998-99. Since, then, it has remained the same. Take wheat. Since 1998-99, wheat has been up to the level of about 70-71 million tons. Take cereals together, since 1998-99, it has been at the level of 190 million tons. 2002-03 was a

bad year. It went down to 160 million tons or so. I pointed out that there has been no major scientific technological breakthrough. After the first Green Revolution, there has been no major breakthrough in the production of rice or wheat or pulses." This is the condition. You are admitting. Your own Government is admitting. How are you going to change the situation? You have to answer this nation. How are you going to change the on-going policies? What is your policy with regard to the situation, which is prevailing in this country, and with regard to the suicide of farmers? How are you going to resolve this issue? You have to give an answer to this nation. That is my humble request to the nation. Then, Sir, with regard to the Minimum Support Price, what is happening? Here, some intellectuals, some experts from Jawaharlal Nehru University and other acadamies who never go to the field are doing heavy exercise from their office and they are coming up with suggestions. Is it helpful to the farmers? That is the question. What is the situation? Not a single support price for the last ten years has met the cost of cultivation, except sugarcane for two years -- he is from Maharashtra -- except for sugarcane, that too for two years, it is almost adjustable. Sir, the average gap in the Minimum Support Price and the cost of cultivation per crop as per the figures worked out to be, following in terms of each crop, over the period of eight years, from 1996-2004. The difference is given in the minus per cent, from the price asked for and granted; paddy: -38 per cent, *bajra*: -48 per cent, groundnut: -32 per cent; cotton: -38 per cent, sunflower, -50 per cent. I do not want to go into other details. This is the situation. So we are discussing about the Minimum Support Price. What is the condition? You have to change it. If we think about all the crops which are being cultivated and the loss to the cultivators, the loss for the cultivators varies from 38 per cent at the minimum to 50 per cent at the maximum. This is the situation. Except sugarcane, whatever cultivating items are there, this is the situation. The farmers are losing everything. Sir, now I come of my State, Kerala. Sir, my State has turned to cash crops. Sir, you must be aware that in my State, 60 per cent of the total gross crop area is meant for cash crops. What happens to the cash crops after this policy? What is the fate of the coffee farmer in the Wayanad district and the Idukki District? In a small district like Wayanad, more than 351 farmers committed suicides. Day-by-day it is increasing.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Even now it is happening.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: What is the reason for the sharp fall in the price of coffee? Everywhere this report is coming. It is the same situation with pepper. You know this country is producing nearly 95 per cent of the total pepper. Kerala is producing for this nation. It is for export and we are getting foreign exchange. For all these export commodities, prices of cash crops have fallen. Is there any programme with this Government to help the cash crop farmers in Kerala? This is the question put by the people of Kerala. Do you have any proposal, any programme, as far as your programmes are concerned? As far as the Ministry of Agriculture is concerned, they are totally unaware of the situation because its hands are tied. He does not have any power. He will say, 'go to the Commerce Ministry.' What is his right on agriculture? You are saying that this does not come under agriculture. You are saying cashew is not agriculture, coffee is not agriculture, rubber is not agriculture, coconut is not agriculture, then what is agriculture? Sir, see the situation. The farmers are committing suicides. The Government is just standing in between. No role for this Government! What is this? The Government has to come out with a specific proposal. There should be a special package for Kerala. The situation is very bad there. The hon. Minister was kind enough to give some help to three districts. But, Sir, we have fourteen districts. Cash crops grow right from Kasaragode to Kakyskkavila. Helping only three districts will not solve the problem. So, give a special package for Kerala. Considering the situation and the variety of crops, especially cash crops and the crop pattern in Kerala, the Central Government has to give a special package and special assistance for Kerala. It should not be delayed. I hope, when the hon. Minister will give reply to this debate, he will announce a special package for Kerala, looking at the problems being faced by farmers in Kerala.

Then, Sir, we have to think about some specific programmes. The first thing is about the institutional loan. What is the role of banks? I don't want to take more time. The Central Government says to banks that they have to give a minimum of 18 per cent loan to farmers. Which nationalised bank is giving 18 per cent loan? What about the private banks? They are giving only 8 per cent or 7 per cent. And, what is the recommendation of Swaminathan Commission? It has recommended to give 30 per cent loan. What is the proposal of this Government? How are you going to provide more institutional loan to farmers? It was reported in *The Hindu* that a farmer owns three acres. He has been asking a loan amount of only Rs. 18,000. It was reported on 8th in *The Hindu*. The report says and I quote,

"I own three acres and needed Rs. 18,000 crop loan. The bank gave me Rs. 5,000. How am I supposed to do anything with that? " This is the news item. He has three acres of land and you are giving just Rs. 5,000! What will he do with Rs. 5,000? For a farmer this bank is giving Rs. 5,000! What will he do? He has no option but to commit suicide. What is this? Are we so inhumane towards the farmers of this country? This is very bad. You have to change the situation.

And, the Swaminathan Commission recommended to give loans to farmers at the rate of 4 per cent. Are you ready to give it? This is my question to the Government. I am expecting a positive reply from the Government.

I now come to the market. Sir, middlemen are taking away 60 per cent and the farmer is getting only 40 per cent. You please enter into the market and do something for them and consider this wholesale price for M.S.P.

Then, I request the hon. Minister to increase the Minimum Support Price. And, the Government should also save the farmers from the clutches of moneylenders. So, Sir, this Government has to come out with some specific proposals. There should be an enhancement in the public inputs. That should be done. You have to provide more irrigational facilities. More infrastructure has to be developed. On these lines, specific and concrete proposals and programmes before the nation should be placed by the Government...(*Time-bell*)...I am just concluding.

Finally, I would like to say that if you forget the farmer then think about those who are sitting on my right. They have campaigned 'India shining minus farmers.' They are sitting there. And, you are talking about only 8 per cent and 9 per cent GDP growth and the there is a zero per cent GDP growth for farmer and he is committing suicide. If you forget the farmer, I don't know the future of this Government. If this policy continues, I cannot help this Government. So, Sir, you have to change the policies in favour of farmer. We are expecting loans to the farmers at the rate of 4 per cent from this Government. I hope the Hon'ble Minister will give a positive reply for the poor farmers who are committing suicide and who are on the verge of committing suicide.

With these few words, I conclude. Thank you.

SHRI N. JOTHI: Sir, I appreciate every word of the hon. Member. Why don't they go to the President and withdraw support to this Government? If you withdraw the support, both the farmer and the country would be saved....(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): That would be more dangerous for the country...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: Why are you standing up here and talking? You must talk about this at the Coordination Committee meeting, to the Congress people, not here...(*Interruptions*)...

SHRI PENUMALLI MADHU (Andhra Pradesh): Sir, what is this?...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Mr. P.G. Narayanan...(*Interruptions*)...Mr. Jothi don't waste time. Mr. Narayanan, please start...(*Interruptions*)...

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the suicides by the farmers is a very serious problem which confronts our country. Almost eight States are affected with this problem. Even in a State, like, Kerala, which has the highest literacy rate and health standards, there had been suicide deaths. If you analyse why there had been suicide deaths in Kerala, you will only come to the conclusion that lack of irrigation facility is one of the main reasons for suicide by the farmers. Deaths have occurred in the Wynad region of Kerala, which falls in the rain shadow region.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Not only in Wynad, but in other districts also.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, this particular area has no irrigation facility. Most of the areas where deaths have occurred -- be it Telangana or Vidarbha -- lack irrigation facilities. So, the suicides by the farmers is taking place in the water-deficit areas and the rain shadow regions. The Government of India is not serious about implementing the 'river linking scheme' between Himalayan rivers and peninsular rivers. The political class in Northern India, especially in Hindi heartland, is sabotaging the river-linking programme for the past several years. States like U.P., Bihar and West Bengal are the principal opponents. Political leaders in these three States talk of nationalism and internationalism, but they are not willing to spare water for the water-deficit areas, like, Vidarbha, Telangana or Tamil Nadu.

One of the reasons behind the naxalite problem in these regions is the lack of irrigation facility. The Central Government, ruled by the so-called nationalist parties, like, the BJP and the Congress are bent upon treating the water-deficit areas as their colonies. When there was a demand from the entire Southern India that Himalayan and peninsular rivers should be linked, our former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, had finalized a Rs. 30,000 crore scheme for linking rivers in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Mr. Vajpayee was only interested in the welfare of the people of Northern India. The same is the case with the Congress Party. That is why BJP will never win the seats from the South India and the Congress Party is slowly losing its ground. Very soon both the so-called nationalist parties will be reduced to the status of regional parties. ...*(Interruptions)*... The Central Government should not act in a partisan manner and should work in the interest of farmers all over the country. ...*(Interruptions)*... If irrigational facilities are provided by linking rivers, like, the Ganges with Cauvery, there will be no suicide by the farmers of Vidarbha or Telangana or Wynad region. These three regions account for ninety per cent of the suicide deaths. So, it is high time that the Central Government should think about implementing the river-linking programme. I would like to suggest to the comrades from West Bengal not to play a second fiddle to the political parties, like, the Congress Party, which is not willing to implement the river-linking programme for the reasons better known to them. I appeal to them to give a helping hand to alleviate poverty in Vidarbha, Telangana and other areas.

Sir, the CPM swears by Karl Marx. And, Marx only preached the rule of the proletariats. So, they should rise above parochial considerations and address the issues of poverty and suicide deaths. Sir, I would like to inform the House that the AIADMK Government headed by my leader, Puratchi Thalaivi, had ensured that there were no suicide deaths in Tamil Nadu despite the fact that Karnataka did not allow water from the Cauvery River. And, therefore, 80 per cent of the crops in the State ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): There are no suicide deaths in Tamil Nadu. There are suicide deaths in Karnataka because.....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Jothi, please sit down....*(Interruptions)*... Mr. Hariprasad, you can speak later, not now. ...*(Interruptions)*... No; no. ...*(Interruptions)*...Mrs. Cariappa, you can speak

later, not now. ...(*Interruptions*)... Don't speak now. ...(*Interruptions*)... Mr. Hariprasad, please....(*Interruptions*)... Mr. Narayanan, you are losing your time. ...(*Interruptions*)... So, you complete your points. ...(*Interruptions*)...

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, they are interrupting. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You continue your speech. ...(*Interruptions*)... You please continue. ...(*Interruptions*)... Don't get interrupted by them. ...(*Interruptions*)... Please complete.

SHRI P.G. NARAYANAN: My Leader, during her rule, launched a unique scheme called the Farmers' Security Scheme for the welfare of farmers and agricultural labourers. One crore and 37 lakh farmers and agricultural labourers were benefited at all stages of their life from cradle to grave. This unique scheme has been done away with by the present anti-agriculturist DMK Government for political reasons. This model scheme, that is, the Farmers' Security Scheme, initiated by my Leader in Tamil Nadu, if implemented all over the country, can prevent most of the sufferings of farmers, including suicide deaths. In foreign countries, like China and the U.S., loans are provided to farmers at the lowest rate of interest. But, in India, we are charging more. So, I appeal to the Government that the rate of interest should be reduced to the minimum. They should not charge more than four per cent rate of interest for the loans advanced to the farmers. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Thank you Mr. Narayanan for sticking to the time. You had eight minutes and you stuck to that. Thank you very much. That is a good example for others also. Shri Manohar Joshi.

श्री मोतिउर रहमान (बिहार): सर, ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN: That is the order. I will call you next. Your name comes after him. You can listen to him, and then, you can speak.

श्री मनोहर जोशी (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस गम्भीर समस्या पर बोलने का मौका दिया। सर, मैं समझता हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के समय यदि सदन में कृषि मंत्री के साथ वित्त मंत्री और खाद्य मंत्री भी उपस्थित होते, तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि यह विषय केवल कृषि मंत्री के हाथ में नहीं है। यह सब काम करने के लिए अर्थ मंत्री कितना पैसा उपलब्ध करा सकते हैं, इस विषय पर आगे की सब बातें निर्भर रहती हैं। इसलिए मैं

4.00 P.M.

समझता हूँ कि आज इस चर्चा के समय वित्त मंत्री का यहाँ उपस्थित रहना बहुत ही आवश्यक था।

सर, मैं खुद किसान नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खेती नहीं है। लेकिन मैं महाराष्ट्र का मुख्य मंत्री होने के कारण खेती के प्रश्न जानता हूँ, इस विषय पर बोल सकता हूँ और जब मैं लोक सभा का अध्यक्ष रहा, तब मैंने इसी विषय पर दो-तीन बार सदन में चर्चा सुनी थी। इसलिए इस विषय के बारे में मुझे मालूमात हैं। विषय कितना गम्भीर है, मेरे यह कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस देश में एक लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई भी देश ऐसा हो, जिस देश में एक लाख लोग आत्महत्या करें और देश में शान्ति रहे। एक कवि ने कहा है,

"आत्महत्या की चिता पर देख कर किसान को
नींद कैसे आ रही है, देश के प्रधान को।"

विषय इतना गम्भीर है, जिस विषय पर न केवल संसद को, बल्कि देश के हर नागरिक को आश्वस्त होना चाहिए, चिन्ता करनी चाहिए, ऐसे विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य इस चर्चा को गंभीरता से लेंगे और इस विषय में सरकार को कुछ सुझाव देंगे और सरकार भी इस बारे में पूरा ध्यान देगी, यही मेरी अपेक्षा है।

सर, इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस देश का प्रमुख पेशा कृषि का है और यहां सब से उपेक्षित कोई है, तो वह इस देश का किसान है। महोदय, मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि हमारे महाराष्ट्र से आए कृषि मंत्री यहां बैठे हैं। वह इस विषय को ठीक तरह से समझते हैं, खुद भी किसान हैं तो किसानों का दुख वह जरूर समझेंगे और इस विषय में जब उत्तर देंगे, तब उन के उत्तर में कोई ऐसा आश्वासन सदन को देंगे कि इस समस्या का पूरा समाधान हो सकेगा।

Sir, the Government have identified 31 districts where farmers are committing suicides on a large scale . In Andhra Pradesh, there are 16 districts; in Maharashtra and Karnataka, there are six districts; and in Kerala, there are three districts....(*Interruptions*)..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Only three!

SHRI MANOHAR JOSHI: Yes, Sir. So, the Government has declared 31 such districts. Therefore, Sir, I know that these are not the only districts -- I know for certain --...(*Interruptions*)...

SHRI SHARAD PAWAR: I said, Chair is for the whole House.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KUREAN): Yes, Chair is for everybody. So, if you increase in every State, I will be very happy.

SHRI MANOHAR JOSHI: Therefore, Sir, I will speak about all the parts of our country where suicides are being committed, but, of course, my thrust will be on the State of Maharashtra from where I come. Sir, in Maharashtra, right from 2001-05, I have seen that the number of suicides is increasing. The total number, according to my knowledge, of suicides during this period is 2,285. I have taken the figures up to May, 2006. Before that also, in some places, suicides were committed but the total figure during 2001-06 is not a small number. I personally feel that a farmer commits suicides when it becomes impossible for him to live. Under the Constitution of India, every citizen of our country has been assured the right to live. It is a Fundamental Right. But, to farmers, unfortunately, this Fundamental Right is not being given, and the matter becomes more serious when I find that after such debates having taken place on a number of occasions in both the Houses, no concrete result is coming out. I would like, therefore, to ask the hon. Agriculture Minister whether he seriously wants to stop farmers' suicides in the country. I am sure and I am confident that if the Government goes ahead with determination, with strong will, to see that these poor people do not commit suicides, it can be done. Sir, I do not want a routine reply from the hon. Minister. I know that at different places, different Committees were appointed. In Andhra, on this issue there was a Committee, namely, National Institute of Agricultural Extension and Management; in Karnataka, Naresh Committee was appointed; and, in Maharashtra, two Committees were appointed --one was Tata Institute of Social Sciences and the other was Indira Gandhi Institute of Development Research. Therefore, my first request to the hon. Minister is, not to appoint any Committee any more, because the appointment of committees has been sufficiently done. They have given their opinions on the issue. They have given their recommendations. But, unfortunately, the Government has not worked according to their recommendations.

Sir, in Maharashtra, it is not that the farmers are only committing suicides, but some farmers -- because they wanted to repay their loans -- have sold their kidneys. There was a case wherein a farmer had sold his child only because he wanted to repay the loan. In such a grave situation, a representation was made to the President of India, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, and in this representation, -- the villagers are from Vadola, a village in Vidarbha, -- they have asked the permission of his Excellency, the President of India, for euthanasia, i.e., that they wanted his permission to kill themselves. Sir, this is a very grave situation. But even for raising such a serious discussion in the House, -- this Session is almost getting over and

we are debating this issue now -- we are waiting till the fag end of the Session. As a matter of fact, this issue should have been the first item of discussion in the House. It should have got the first priority among the items which was supposed to be discussed in the House in this Session. But, unfortunately, it could not be done because the farmers have the last priority, not only outside but even in this Session also. Sir, these farmers wrote to the President that they would like to end their lives instead of suffering crop losses every year. It means, they were prepared to die, and they wanted the permission of the President of India in that regard. If this is the plight of the poor farmers of this country, I don't know what the Government is going to do. I have to make a charge against the Government that they are not sincerely trying to solve this problem; and they are also not seriously attempting to stop suicide being committed by farmers of our country. ...*(Time-bell)*... Sir, I have just started. Sir, firstly, the debated started too late. We can sit late. You can take the sense of the House. I am sure that everybody would like to sit late. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): See, Manoharji, there are 17 more speakers who are yet to speak. That is why I am saying this. Please try to be brief. Try to complete it, as soon as possible.

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, I will try to be brief. Sir, the Chief Secretary of the State of Maharashtra was fined for not giving the necessary information about the death of people, about the number of suicides, to the court. Is the Minister aware of this that finally on their request for pardon, they were pardoned by the court? But the Chief Secretary and thirteen other IAS officers were punished only because they could not give the information at right time. Sir, once Gandhiji had said, "The poor Indian farmers have no option but to do farming activity. He cultivates the land which he inherited from his ancestors and the agricultural activities are not profitable. But by cultivating the land, the farmer is becoming poor and poor day-by-day." So, it means, the great leader like Mahatma Gandhi, also knew the plight of the farmers.

Sir, I would only talk about the points which I want to make. The reasons for suicides by the farmers are enumerated by the Minister himself. He had said, natural calamities cause high indebtedness, and the reason for that is, failure of crops, uncertainty of monsoon, non-availability of term loans, high rate of interest, highest rates of interest of the private moneylenders, diversion of loan for marriage, sickness, education, etc.,

mono-crop, no supplementary income other than agriculture and much pressure on land because of the growing population.

Sir, I would like to add only two to three points to these. One of them is, the Plan outlay in agriculture, which is going down every year. Is it not necessary, and does the Government not know, that this Plan outlay needs to be increased? If you look at the Plan right from 1951, during 1951-56 it was 14.9 per cent of the total Plan; now, if we look at the Tenth Plan, the Plan outlay has gone down to 5.2 per cent. That means that for agriculture, the outlay is not increasing, but, unfortunately, going down. Therefore, would the Agriculture Minister assure the House that the Plan outlay for this Five Year Plan and the next Five Year Plan would increase and not go down?

Sir, irrigation backlog in Vidarbha has also caused a number of suicides, as also the cotton price rise mechanism in Vidarbha, which has already been mentioned by earlier speakers. I have with me a copy of the manifestos of the Congress Party, both for the Central and State Governments. I would not take the time of the House by reading out this manifesto, but the Congress Party had promised that they would spend the maximum amount of money for farmers. What has happened to that? This is the manifesto of the Government of Maharashtra where they said that electricity would be given free of cost; the then Chief Minister is not present in the House now, but he had promised that electricity would be given free to the farmers. What has happened to that? These manifestos are deceitful and the farmers are dying because the Congress Party promised them lots of things, which they did not honour.

Sir, because of paucity of time, I would only suggest a few remedies. If the Government wants to help the farmers and stop the suicides, these remedies must be followed. And if that is done, I feel confident that suicides could be avoided. If the Government is serious about stopping farmers' suicides, the best and immediate remedy would be to waive off the debts that they owe till date. My request to the hon. Minister would be, let us not make it a point of prestige and let us waive off the total loans given to the farmers. If that is done, at least, during difficult times like this, I am sure, the farmers of the country will not commit suicide.

Sir, as regards interest on the loans that they have taken, I would say that it could be reduced, and the rate of interest that I have suggested is four per cent. It is most shocking that you could get loan to purchase a

Mercedes car in Mumbai at the rate of six per cent, while the farmers have to pay 11 to 12 per cent. I don't think justice is being done in any manner. This needs to be taken care of. Here, I would like to mention that in Maharashtra, there is a case where one of the moneylenders is an MLA himself, and the rate of interest charged by him is not less than 30 per cent.

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र): सर, ऐसा कोई एम.एल.ए. नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI MANOHAR JOSHI: I am not mentioning any names. I don't wish to know all the names.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): He has not mentioned any name. How do you know which MLA it is?

श्री दत्ता मेघे : सर, महाराष्ट्र के एम.एल.ए. का उन्होंने कहा है...**(व्यवधान)**... सर, महाराष्ट्र का एक भी एम.एल.ए. ऐसा नहीं है, एक भी मनी-लेंडर नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... वह ख्वामख्वाह एम.एल.ए. का नाम लेना चाहते हैं।

श्री मनोहर जोशी : मैंने नाम तो लिया नहीं अभी तक ...**(व्यवधान)**...

श्री दत्ता मेघे : एक भी ऐसा एम.एल.ए. महाराष्ट्र में नहीं है।...**(व्यवधान)**... किसी भी पार्टी में नहीं है, ऑपोजीशन में भी नहीं है और रूलिंग पार्टी में भी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, this was not denied. Over and above, it was said that the Chief Minister of Maharashtra helped that MLA when he was in difficulty. But, I am not going into that controversy. But I am not going into this controversy. So, the rate of interest has to be reduced; the loan amount has to be totally wiped out. I am sure, if this is done the farmers can be saved. My last point is about the Prime Minister's package and the truth about it. The Prime Minister came to the State of Maharashtra, particularly Vidarbha region. I appreciate his visit. He along with the Agriculture Minister, and also the Home Minister probably came and gave a package. His package was not appreciated at all. He provided Rs.712 crores for overdue interest. But 50 per cent of that ..*(Interruptions)*..

SHRI DATTA MEGHE: It was Rs.3750 crores. ..*(Interruptions)*..

SHRI MANOHAR JOSHI: I am speaking point by point. ..*(Interruptions)*.. Out of this amount, 50 per cent was to be shared by the State Government. Rs. 1300 crores were for redistribution of overdue loan. It was not seen whether it is beneficial for the farmers or the cooperative banks. Sir, additional credit loan of Rs. 1275 crores was given from NABARD. NABARD has enough money. The question was of N.P.A., otherwise there was no problem. Sir, Rs.2177 crores were provided for

irrigation activity, and in the package finally a number of items, which are provided in the Budget every year, were there. Therefore, ultimately, this amount of Rs.3750 crores was not the amount in reality. The amount, which they provide in Budgets, was also shown and the Government tried to pretend as if they were giving a big relief to farmers, which was not really true. Therefore, Sir, I would like to request the Government that apart from the loan and the interest, seed should be made available to the farmers; customs duty on cotton coming to India should be increased; Irrigation Special Fund has to be given; electricity should be made freely available to farmers. If these few things are done, I am sure that the suicide by farmers can be stopped. But, Sir, let me warn the Government, before I conclude, if this is not done, I am sure, that farmers will take law in their hands; and farmers are not going to tolerate the incapability of the Government to provide them relief. Therefore, the Government will have to act now. It is my earnest request to the hon. Minister to act now and see that farmers get relief. Thank you.

श्री मोतिउर रहमान : उपसभाध्यक्ष जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, सबसे पहले मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह हमारी खुशकिस्मती है कि हिन्दुस्तान में UPA गवर्नमेंट आई और उसमें कृषि मंत्रालय की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ् में आई जो हिन्दुस्तान के खेल के मैदान से लेकर सियासत के मैदान तक और हर चीज़ में एक अनुभवी व्यक्ति है। आज क्या कारण है कि किसान सबसे ज्यादा परेशान है, इसके बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए और इसमें दलगत राजनीति और अन्य क्षेत्रीय चीजों से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर देश को मजबूत करना है, अगर देश का विकास करना है, अगर देश में अमन-चैन कायम करना है तो सबसे अहम मुद्दा किसान का है। अगर किसान खेती नहीं करेगा, तो देश का आर्थिक विकास नहीं होगा, देश में अमन-चैन कायम नहीं होगा। आखिर क्या कारण हैं कि आज देश का किसान सबसे ज्यादा परेशान है? मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं जानता हूं कि आज छोटे किसान खेती करना नहीं चाहते, वे रोजगार करना चाहते हैं, बाजार में दूसरे काम करके अपना पेट भरना चाहते हैं। खेती में जितनी लागत लगती है, उतनी उपज उसे अपने खेत से प्राप्त नहीं होती है। यह एक गंभीर विषय है। हिन्दुस्तान को एक ऐसे कृषि मंत्री मिले हैं, निश्चित रूप से वह इस पर प्रभावकारी ढंग से काम करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आखिर फिर कारण क्या हैं? त्रुटियां कहां हैं? कहां पर एक-दूसरे से मेल की कमी है? क्या वित्त मंत्री और कृषि मंत्री में कहीं न कहीं टकराव की स्थिति है? आखिर कारण क्या है? इस चीज़ को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि इस देश में अखबारों अथवा दूसरे जराय के जरिए से मालूम होता है कि इस देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब किसान के पास अपने बाल-बच्चों की परवरिश के लिए उपज नहीं होगी, दूसरा कोई काम वह कर नहीं सकता है, अपने बाल-बच्चों को अच्छे स्कूल या कॉलेज में वह पढ़ा नहीं सकता है, और तो और अपनी

उपज से वह अपनी जिन्दगी में अपनी बेटियों की शादी भी नहीं करवा सकता है, तो फिर इस हिन्दुस्तान के अन्दर इससे अधिक बड़ा और गंभीर मसला और क्या हो सकता है?

आज मूल्य वृद्धि हो रही है। आप किसानों को उनकी उपज की मुनासिब कीमत नहीं दे रहे हैं। आपने गेहूं का दाम 610 रुपये निर्धारित कर दिया है और फिर आप विदेश से हिन्दुस्तान में 900 रुपये के दाम में गेहूं मंगवा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जितने भी बड़े-बड़े सेठ व साहूकार हैं, उन्होंने किसान के गेहूं को खरीद करके गांव-गांव एवं बाजार-बाजार में होर्डिंग कर दिया। एनडीए की सरकार ने होर्डिंग को रखने का एक कानून बना दिया था। देश को बर्बाद करने की जिम्मेवारी तो उन्होंने ले ली कि होर्डिंग का कानून बना दिया। जिसे जितना माल रखना हो, रख ले। उस समय उन्हीं लोगों की सरकार थी, लेकिन आज जब तक आप होर्डिंग को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप उस कानून को तोड़ने का काम नहीं करेंगे, जब तक आप उस कानून को बदलने का काम नहीं करेंगे, उस समय तक मैं नहीं समझता हूं कि आप इस देश में महंगाई पर कंट्रोल कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक किसान के खेत का सवाल है, उसके लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने हर खेत के लिए पानी का वायदा किया, लेकिन आप किसी भी खेत को पानी देने की स्थिति में नहीं हैं। मैं बिहार की बात करना चाहता हूं। बिहार में जितने भी सिंचाई कैनाल बने, उनमें से कोई भी कैनाल आज चालू नहीं है, उनमें कहीं पानी नहीं है। अपनी प्लानिंग के तहत आपने जितने भी ट्यूबवैल वहां लगवाए, उनमें से कोई ट्यूबवैल भी चालू नहीं है। आप समझ सकते हैं, आज वहां पर सुखाड़ की स्थिति है, वहां पर पानी नहीं है, वहां का किसान आज भुखमरी की स्थिति में है, उसका भविष्य अंधकार में है। इस पर आखिर आप क्या काम कर रहे हैं? आज वहां के किसान व मज़दूर पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में वे क्या करेंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): एनडीए के समय में ऐसा कोई कानून नहीं था ...**(व्यवधान)**... हमसे गरीब कोई नहीं ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Pany, please, don't interrupt. पणि जी, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि : आप हमें यह बताइए कि एनडीए के समय के कौन-से कानून में होर्डिंग को बढ़ावा मिला है ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Pany, please ...*(interruptions)*... ठीक है, आप बैठ जाइए ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि : मुझे कानून का नाम बताइए ...**(व्यवधान)**... इस तरह के गैर-जिम्मेदार वक्तव्य नहीं होने चाहिए ...**(व्यवधान)**... This is highly irresponsible statement.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Rahman, please continue. Please, try to wind up. समाप्त कीजिए।

श्री मोतिउर रहमान : आज बिहार में कोई भी ट्यूबवैल चालू नहीं है। आखिर फिर किस तरह से आप सुखाड़ का मुकाबला कर सकते हैं? कृषि मंत्री जी, क्या आपने वहां के किसानों की हालत देखी है? बिहार की उपज पहले कितनी अधिक थी और आज कितनी नीचे स्तर पर चली गई है, आपको इसकी समीक्षा करनी चाहिए। आपको बिहार के किसानों के प्रतिनिधियों के साथ और बिहार सरकार के साथ बात करके यह देखना चाहिए कि कमियां कहां पर हैं।

जहां तक बिजली का सवाल है, वहां पर बिजली भी नहीं है। वहां पर बिजली कहीं पर भी नहीं मिलती है। किसान डीजल से काम करता है, उस डीजल का भाव बढ़ता जा रहा है और जो उपज होती है, उसका उतना दाम उसको मिलता नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि किसानों को फैसिलिटी के लिए कम इनटरेस्ट पर लोन देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर किसानों को और इस देश को मजबूत करना है तो किसानों के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर किसान की उपज का दाम उससे अधिक जब तक नहीं मिलेगा तो किसान को दिलचस्पी नहीं होगी तो फिर कैसे चल सकता है। जब तक उसके काम आने वाले सामान पर आप बैंक से लोन नहीं दिलवाएंगे, उसको मदद नही करिएगा, उसको प्रोत्साहन नहीं दीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ...**(समय की घंटी)**...

आप दूसरों से भी मुकाबला करके घंटी बजाया करिए। अगर दूसरे बीस मिनट बोले तो हम पांच-दस मिनट नहीं बोलेंगे। इस कुर्सी पर से इंसाफ मिलना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0 जे0 कुरियन) : सुनिए, आपकी पार्टी का टाइम पांच मिनट था, लेकिन आप आठ मिनट ले चुके हैं।

श्री मोतिउर रहमान : हमको बीस मिनट बोलना है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0 जे0 कुरियन) : नहीं-नहीं, बीस मिनट नहीं, दो-तीन मिनट।

श्री मोतिउर रहमान : जहां तक किसानों के आने वाले फर्टिलाइजर का सवाल है, यह भी सही ढंग से नहीं मिलता है, उचित दाम पर नहीं मिलता है। बिहार के किसानों को ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। आप समझ सकते हैं और उसमें भी, फर्टिलाइजर में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट है। फिर इसका भी सही तरह से इंतजाम आपको करना चाहिए। बीज के मामले में आप कहते थे कि हम किसानों को उन्नत बीज देंगे। आपके पास जितने कृषि फार्म हैं, बिहार में सब बंजर पड़े हुए हैं। पहले उनमें बीज तैयार होता था। अब बड़े-बड़े लोगों ने बीज का रोजगार कर लिया और आपने किसानों को कह दिया अपना बीज इस्तेमाल मत करो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो किसान अपना बीज रखते थे, उसमें ज्यादा उपज होता था, आज दूसरे का महंगा बीज मंगा करके खेती होती है, जिससे खेत बंजर होता जा रहा है तथा उसमें अधिक फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित मांग माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0 जे0 कुरियन) : सिंचाई के बारे में आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री मोतिउर रहमान : बिजली का इंतजाम किया जाए, बैंक से मुनासिब सूद पर किसानों को सामान दिया जाए। हमारे मिश्र जी ने कहा कि बराबर इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार अच्छी लाइन पर चलती है तो बीच में ये लोग आ जाते हैं। तो गलत नीति को लेकर के देश के पांच वर्ष में, बीस वर्ष के काम को ये लोग बरबाद कर दते हैं। इसलिए अगर देश को सही ढंग से चलाना है तो एक ही पार्टी, यू0पी0ए0 गवर्नमेंट बराबर रहे तथा शरद पवार जी जैसे कृषि मंत्री रहे तो मैं समझता हूं कि देश का भला होगा, किसानों का भला होगा। ये लोग किसान विरोधी हैं, ये बड़े-बड़े सेठ साहूकारों के प्रतिनिधि हैं, किसानों का प्रतिनिधि बनकर नहीं आते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने इतनी देर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री एम0 वेंकैया नायडु : हम लोग यहां किसानों की आत्महत्या के बारे में डिसकस कर रहे हैं। इन्होने पचास साल राज किया, दुर्गति की है, सबको मालूम है।...**(व्यवधान)**... पचास साल एक ही परिवार है। ...**(व्यवधान)**... हमारा पांच साल का रिकार्ड देखे, आप क्या बात कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Arjun Kumar Sengupta. Be brief please.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, we can all appreciate the intensity of feeling on this subject which has been expressed by all concerned. May I be permitted to talk something without any partisan position and state what are the problems and how those problems have to be tackled?

Sir, the farmers' suicides are not new, although this has been happening over the last few years at a rate much greater than before. And, temporary actions are taken. But, it can always be said that these actions are not enough; the provision the Prime Minister made is not sufficient. This can always be talked about. I am not getting into those discussions today. What I would like to talk about are the methods to prevent farmers' suicides, that is, go into the problem directly.

Sir, one of the main issues that we should consider in talking about the problems is that we should not be guided by solutions which appear to be solutions, but which are really not solutions over a period of time. For example, the problems of Bt Cotton. I am mentioning this because I have full sympathy with those NGOs and organisers who have found many problems with Bt cotton, because it increases dependence on water, dependence on fertilizers. It has also problems related to environment and attacking other kinds of insects. All these problems are there. But, the fact of the matter is that the Bt cotton is accepted by the farmers. They buy this Bt cotton. So, what we should do there is not to

stop the purchase and sale of Bt cotton or spread of technology or even trials. What we should do is to spread the story; the adverse effects of this should be told categorically, in different ways, to the farmers that if you go for this, you will be facing problems of water, facing problems of fertilizers, facing all the other problems. If, in spite of that, a farmer goes for that, I don't think we should try to stop that because that would be putting the clock back on technological progress. But we must, like cigarette-smoking, be able to point out the problems that are there.

Similarly, if I may say so, is the question of import duty. This has been raised by several members that import duty should be imposed immediately. We must think about it because if you impose import duty, it would have an adverse effect on textile production. This is something which you must consider. What is the best way of protecting the farmers' interests? It is not necessarily by preventing imports; but by trying to help them to meet the competition from imports, if the imports are coming in great quantity in our country.

There is also the problem that the monopoly procurement has been stopped. We should not try to re-introduce that. But, we should have some alternative mechanism of providing a procurement network when the prices are going down. These are the ways of looking at this problem, not what appears to be the immediate problem.

Similar is the question of Minimum Support Price. I must point out -- I am quite sure that people are aware of it, but it needs repetition -- that Minimum Support Price is needed when the prices are going below the cost price, when the market prices are such that the farmers have the disincentive to carry on production. The calculation of Minimum Support Price is based on cost plus. Now, some questions were raised -- I think, I would not mention the name -- that the experts don't know anything. They are calculating these things on the basis of some paper exercise. I cannot comment on that. They must have done these exercises properly. But, the Minimum Support Price is not the same thing as market price. And, if the Food Corporation of India or the Cotton Corporation of India, whatever is the market procurement agency, have to procure products for supply, for buffer stock, they should be able to buy from the market, at a market price. Earlier this issue was there for market intervention the difference between Minimum Support Price and the Purchase Price. This should be reintroduced, and our public sector procurement agency should go into the market.

I must also mention here about the Minimum Support Price. My CPI(M) friend talked about it. If you do not have the method of procuring from the *mandi*, it will only benefit the rich farmers. The agency is not there today. You should ask the Food Corporations to go to the village *mandi*, and buy it from the farmers. If you really want to do that, you should not talk about raising the price. Without the institutional mechanism, it would only help the rich farmers who have surplus and buy from the farmers in villages. What I am trying to say, Sir, is that we must have a proper institutional mechanism to tackle the problems of the poor farmers, the small and marginal farmers. Sir, these are the farmers who are suffering the most and are in distress; and they are actually committing suicide. Even in the State of Punjab, which is relatively rich, there are suicides there, and, again, these suicides are within the small and marginal farmers. The problems of the small and marginal farmers -- it is also the problem of any poor person in our country -- are that they do not have access to credit; they do not have access to market; they do not have access to technology; and they do not have access to water. The whole system is against that particular group of people -- whether it is in Punjab or Maharashtra or even in West Bengal. If I may point out, this is the situation. The whole approach to agriculture has to be now based on small and marginal farmers.

I am afraid, Sir, this Government, which is supposed to look after the poor people, is talking about a plan, which does not say anything of that kind. There is an Approach Paper which has come out, and I am sorry to say that Approach Paper does not give any idea of how the problems of small and marginal farmers are going to be tackled. I hope when the actual plan will be written, the Agriculture Minister would see that a proper plan for the small and marginal farmers is formulated. Most important requirement for that is budgetary provision. Unfortunately, the Finance Minister is not here. The financial provisions for agriculture should increase substantially, especially when this Government has come to power with a clear promise of helping the agriculture. In spite of that, this budgetary provision for agriculture has not actually gone up. The agricultural credit has almost overwhelmingly gone to horticulture and not for crop production. Something is going wrong. Something is going wrong in this system, which is trying to talk about the poor people but is helping only the rich farmers, traders and the correspondingly rich people. So, we need an approach to a different kind of plan, and I hope the Agriculture Minister would be able to tell us the outlines of that. (*Time-bell*) Sir, I will conclude.

One is the question of distress. The distress of small farmers is not only that they are not getting the right prices, not only that they are unable to sell their products, but also they do not have any social security. Time and again, this question has been raised that if a farmer falls sick, then by one sickness, the whole family becomes destitute. Three-fourths of our farming population have a consumption expenditure of fifty cents a day. Sir, I must mention this for everybody to realise this seriously. One dollar is considered to be the line of extreme poverty all over the world. Two dollars per day is the international recognised line for poverty. Three-fourths of our farmers have only 50 cents per day, that is, half of what is known as extreme poverty. These people have to be protected in some form of social security. Therefore, we must consider social security of the farmers, health insurance of the farmers as an essential element.

Finally, the question of market prices. We forget that the farmers are also buyers of these products. They buy from the market. The wheat largely goes to the farming community. They do not sell extra wheat. They are facing a market where if your Public Distribution System does not work, they are suffering enormously. And I am afraid this Public Distribution System is not working properly. I have raised this issue earlier. The Agriculture Minister once told us that there will be no dilution of the Public Distribution System, but I have the numbers to show (*Time-bell*) that there is a substantial cut back on the Above Poverty Line Public Distribution System where the price is Rs.6 per kilogram whereas the market price is Rs.11. This is completely a wrong approach because we must increase the supply of wheat in the market, through the PDS, and if there is any cut back, that should be restored.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, please.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Just one minute, Sir. I must mention this because the Finance Minister said that the solution to this problem is to increase the supply in the market. He kept on saying that this is the supply side management that has to be looked forward to and that supply can be ensured only if the PDS is protected and full supply to the APL purchasers takes place. The APL purchasers are largely in the rural areas. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you Mr. Sengupta. Now, Shri Rahul Bajaj.

SHRI RAHUL BAJAJ (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to make my maiden speech. My family comes from Wardha and Shri Janeshwar Mishraji, who is not here, mentioned about the *Ashram* of Gandhiji which is Seva Gram and that is where my late grandfather Jamnalalji invited Gandhiji in the early 1930s from Sabarmati near Ahmedabad. Mr. Vice-Chairman, Sir, a lot has been said about this subject. I would try not to repeat it and one of the ways, I will do it is by concentrating on my homearea which is Vidarbha and which is the cotton bowl of the country. So, I will talk about cotton, Vidarbha and then, later on, a little bit about the economy and the society.

We have heard that suicides primarily are by small and marginal farmers. It is very correct. We have also heard that like any commodity, Mr. Vice-Chairman, an industrial commodity, in the services sector, IT or otherwise, the only way you can be sustainable and you can survive is when the selling price exceeds the total cost of production. Keeping in mind States like Maharashtra and Vidarbha where less than five per cent of the land is irrigated, the chances of crop failure are obviously very high. So, if you take the cost of production of cotton in Maharashtra and Vidarbha, it is much, much higher than other places including a State like Gujarat. Whenever a human life is lost unnaturally, it is a tragedy. But when someone takes his own life, in my view, it is a catastrophe. And yet, in recent years, we have seen thousands of farmers are taking their lives with numbing regularity. What should be done? Costs have to come down or selling prices have to go up and for the time being, I would not worry about the consumer and the customer; though on onion prices, Governments have changed. But let's leave it aside because here, we are not talking of the production of an industrial commodity, we are talking of 65 per cent of the population of this country. So, they are consumers as well as producers. We have heard enough that if you don't take care of the farmer, how will India move forward? I fully share this view because we are all inter-dependent. The Minimum Support Price for cotton, generally, in some States, has been lower than the cost of production. As Shri Arjun Senguptaji was rightly saying, MSP is done to ensure that a farmer, at least, gets something more cost-plus approach. Mr. Vice-Chairman, Sir, the 2004-05 report of the Commission for Agricultural Costs and Prices estimated the cost per quintal of cotton -- I won't give too many figures, only three figures -- at Rs.1643 in Gujarat, Rs.2229 in Karnataka and Rs.2216 in Maharashtra. But there was naturally only one Minimum Support Price and, in that year, that was Rs.1916. Cost being above MSP does seem to explain and,

at least, it is one major reason for the distress in Maharashtra and Karnataka. In Gujarat, because the cost was lower than the MSP, perhaps we have not heard of that many, if any, suicides from there.

So, the first point I am making, Mr. Vice-Chairman, Sir, is that you can take care of debt items--and I will come to that in a moment--but all those are temporary measures of help today, tomorrow. If you are to keep selling your product, in this case, cotton, or any other agricultural product, at a price lower than the cost of production, no amount of debt can take care because ultimately, the debt has to be repaid. एक बार माफ कर देंगे, दो बार माफ कर देंगे, इन्टरेस्ट को भी छोड़ देंगे, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? चाहे बजटरी सपोर्ट यह काम करे, बैंक करे, ऊपर से तो पैसा नहीं आएगा क्योंकि यह तो टैक्स पेयर्स का पैसा है। So, ultimately, he must make a profit. Yes, I will talk a little about the private moneylender, about whom much has not been said except some passing reference by a few speakers.

I may also mention, Sir, that in 2004-05, the Maharashtra Government offered prices of around Rs.2,500/- per quintal. Very good. But, then, it became unsustainable for their budget. Sir, in 2005-06, they reduced the price to Rs.1,918/-. I have already referred to the cost of production, in Maharashtra, of cotton, which was higher than Rs.1,918/-. And the result is for all of us to see. Of course, Sir, I cannot say to my Agriculture Minister that he has been unfair to Vidarbha and partial to Western Maharashtra. That would be a very unfair comment, Sir, because I come from Vidarbha and he comes from Western Maharashtra! But that is a fact of life. Even when we had a Chief Minister like Vasantrao Naik, who was from Vidarbha, probably not much was done because he did not get that strength. Private moneylenders, Sir, when do they lend money? When the banks and the cooperative societies do not lend. The marginal farmer has not paid his loans. He cannot get loans elsewhere. However, he is now also supplying inputs. He is also now buying the output. So, he has a stranglehold on the farmer. I understand that, nowadays, they are charging as much interest as 60 per cent per annum, Sir! I think, Manohar Joshiji or someone else mentioned 30 per cent. Sometimes, they charge 60 per cent. At 60 per cent, even the best-run industrial establishment will close down. Whether he charges two per cent, four per cent or six per cent, is not the point. The question is-- I don't understand it, Sir; maybe, the Agriculture Minister will tell me--that there is the Bombay Moneylenders' Act, 1946. Our Agriculture Minister was, probably, four years

old at that time, Sir, and I was a little older. Now, that Act says that if the moneylender is not licensed, he cannot recover his loan; he cannot go to courts, and if he is licensed, the total outstanding amount cannot be more than twice the loan. And it also specifies the rate of interest. I do not know why my State Government is not taking advantage of that Act. There must be some reason for that. Rajnathji rightly referred to the WTO. I do not want to take too much time on that. I would only say this. When we talk of market prices, we talk of normal market prices. The international cotton prices are not normal, 4 billion dollars. Rs.18,000 crores is the subsidy provided by the US alone to its cotton farmers only; we have heard Shri Rajnath Singh. I do not know whether he said total agricultural subsidy it is 350 million dollars. It is 350 billion dollars. The total subsidy for farmers by the OECD countries is 350 billion, not million. Cotton farmers get Rs.18,000 crores in the US. My farmer, in Vidarbha also, maybe, he can compete with the American farmer, but he cannot compete with the United States Treasury. Kamal Nathji, in some other context, rightly said that the farmer can compete with the wheat imported, or any other commodity, in the agricultural area, but he cannot compete with the subsidies which a country like the United States provides. And because of this, I come to my recommendations, Sir.

[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

In the short-term recommendations--Mr. Arjun Sengupta said about the import duty--first of all, Sir, I am referring to the import duty on cotton which is not produced in this country. If it is not produced, nobody gets hurt. And the textile mill people are very influential people. You know, industrialists, big industrialists are not people like me, Arjunji. So, fine. But when cotton is produced in this country, if we import cotton from a country which subsidises its cotton farmers, then we must have an anti-dumping duty. I don't understand why it is not there. It would be WTO compliant.

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SHANKERSINH VAGHELA): We are not importing cotton from countries which are subsidising it.

SHRI RAHUL BAJAJ: Fine. If there is no cotton import from such countries, fine. I am just saying, if there is cotton import, which is a subsidised variety, then I must have a countervailing duty.

Sir, why don't we hear about suicides from Gujarat? One reason is that, obviously, 40 per cent of the land is irrigated. In Vidarbha, it is four per cent. It is important that in Gujarat farmers normally have some other

income from dairying, vegetables, etc., which they supply to the nearby industrial centres. Probably, that does not exist in Vidarbha.

Sir, I believe that the relationship between agriculture and industry is symbiotic. A prosperous agriculture develops industry and a prosperous industry develops agriculture incomes. I strongly believe that India can't move forward, unless its farmers move forward; and the growth is only of value, when it is inclusive.

Sir, the irony of the fact is that the cotton economy in our country has good growth in demand ahead of it. The domestic market is growing and with the end of Multi-Fibre Agreement, though China has benefited quite a bit, a very large market has opened abroad for us also. Our exports of cotton clothes are growing and we have further potential to grow.

Mr. Chairman, Sir, may I suggest six short-term measures and two medium-term measures.? I am not referring to the long-term measures because John Maynard Keynes said, "In the long run, we are all dead". My six short-term measures--some of them are being implemented or will be implemented or have been announced by the Government--are: One, a one year moratorium on repayment of debt owed to private money-lenders. This has been done for eight months or so by the Andhra Pradesh Government. A two-year moratorium--I am saying only a moratorium because I don't want to start a bad example of non-payment of loans--on repayment to cooperative institutions and banks, especially, by small farmers whose holdings are below two hectares and whose loan is below Rs.1 lakh. But the banks must step in to help such farmers. Two, Immediate disbursal of, at least, Rs.1 lakh to the families of each farmer who has committed suicide. I don't want this to be misused. If you ask ten kinds of questions like whether he has committed suicide or whether he was murdered or whether he died in an accident, he will never get this money. Three, there should be a declaration that private money-lenders and the private sector man can't charge interest above a certain rate, whatever the Government thinks fit, and I would even say 20 per cent. Four, all land transfers that have been made in the last two or three years should be reviewed, and if the cause of such land transfers was exorbitant interest rate, then it should be considered, within the laws of the country, whether that transaction can be invalidated; and, of course, the lender should be repaid his loan. Five, a review of the Minimum Support Price of cotton and the appointment of the Maharashtra Cotton Procurement Federation, in addition to the Cotton Corporation of India, as an agent to

procure cotton at the MSP. Six, anti-dumping duty--I referred to it already--should be levied on cotton, if cotton, which is subsidised, is imported.

Sir, the two medium proposals are: One, to increase irrigation in the region through irrigation schemes and village level initiatives to conserve rain run-off. Mr. Sitaram Yechury and Shrimati Brinda Karat are not here. Two, as I said, the relationship between agriculture and industry is symbiotic. So, we must encourage industrialisation in these areas.

Sir, we have 60 per cent of the population living on agriculture. America has only two per cent of its population living on agriculture and it produces more than what it needs. Today, we are employing 60 per cent in agriculture. But we can't continue to absorb 60 per cent in agriculture. It may not be two per cent. It may come down to 40 per cent or 30 per cent or 20 per cent. Where will they go? They have to go to the industry and they have to go to the service sector which are complementary to each other. So, I would suggest that we must encourage industrialisation in these backward areas by providing infrastructure. This is what is required. Industry does not want money incentives. In fact, that distorts our decision-making. In Himachal and Uttaranchal, I was against extending the benefits given by three years; that distorts the situation. Even I am going there. I didn't want to, but there are such benefits that you cannot ignore them. Sir, in these backward areas, if we provide the right infrastructure, and, my friend may not like it, a flexible labour policy -- don't give them in areas where I am already there, but only in those backward areas --then, a lot of industries will come up in these areas, and both agriculture and industry would benefit. What we need are a few but effective measures...

MR. CHAIRMAN: I think this is your last page.

SHRI RAHUL BAJAJ: Last but one page, Sir. I will take five to ten minutes more. Sir, you have got a very good eyesight, better than my eyesight.

What we need are a few, but effective measures. In our governance, we have come to be obsessed sometimes with the form, and we are unmindful of substance. There are, for example, 29 Government Resolutions of the Maharashtra Government on Cotton as of 24th May, this year. I don't know whether they are only on paper. I may add that someone has to be responsible to implement all these plans. Right now, everyone from PMO downwards is responsible which means, perhaps, no one is responsible. I would suggest, especially for Maharashtra, that a

Cabinet Minister level or a Deputy Chief Minister level person is appointed, and this position be created in Maharashtra with the sole responsibility of improving the state of agriculture in Vidarbha. A young and a dynamic person -- he is not here; otherwise, he will shout at me -- like Shri Praful Patel, who is considered to be one of the best Ministers in the Centre, should be given this responsibility.

Sir, since this is my maiden speech, I seek your indulgence in saying a few words to outline my broad perspective on our economy and society. We pledged at our independence to take India forward. We have taken it forward, but nowhere near as much as it can be taken, or where it was capable. The glass is still only half filled. We still have unspeakable poverty, which was referred to by Dr. Arjun Kumar Sengupta, where 28 per cent of our people, that is, 300 million people, are living on less than one dollar a day, a poverty which crushes human dignity, stalking our land. Our poor governance, in my view, has, by and large, been a drag on our development. It is the tenacious spirit of India, alive in the hearts and minds of every Indian, whether he is a worker, farmer, businessmen, entrepreneur, or, I do not know whether I should say, politician, and their spirit, hard work and entrepreneurial ability have taken and continue to take our country forward.

I believe that we stand at a propitious moment in the history of our nation. While we acknowledge the challenges, -- there are many challenges -- a world of opportunity also awaits us. As you know Sir, in the world, India is not just a flavour of the week or the month or the year. We are the flavour of the times. Previously, it was only China. Now it is China and India. Both in the services and manufacturing sector, we are poised to gain from the developments in the world economy. We are becoming internationally competitive despite the serious handicaps of lack of infrastructure, right from social infrastructure, health, education, drinking water, sanitation and, of course, physical infrastructure. The key reason, however, for my optimism, as I said, Sir, is the quality and entrepreneurship of our people. Though low as a percentage of our population, we must strive to increase this. We are the world's largest pool of smart, hardworking manpower, be it in IT, manufacturing or finance. And, this is very important and we are conscious of it, that demographically, we will remain a country of the young even in 2025. We have to ensure that we encash this demographic dividend by investing in their education and their skills. With education and skill, India will become a great country; we shall

5.00 P.M.

capture the world in the next 25 years. But if our youth are not educated, are not skilled, instead of becoming a great asset, they will become a great liability. Sir, we need good governance to achieve these goals of inclusive economic growth. This will come from changes at the top and pressures from below. The pressure from below will increase, as economic and social development make our people more self-assured and more articulate. The reopening of the Jessica Lall and Mattoo cases, under intense public pressure, bodes well for our democracy. Democracy is not just elections. Democracy is active participation by every citizen in the affairs of the state, and the state exists essentially to provide public goods and services to its citizens.

In this connection, in passing, Mr. Chairman, Sir, -- I have no time to go into details -- I would like to add to ensure that we can take hard decisions. The Lok Sabha and all the State Assemblies should go to elections simultaneously; co-terminuously, and only once in five years. To ensure this a vote of no-confidence in the Leader of the House, the Chief Minister or the Prime Minister, should be, like Germany, which is a democratic country, accompanied by a vote-of-confidence in an alternate party or person.

So, Sir, quality of leadership is crucial in determining outcomes. Leadership is not just a matter of charisma or showmanship or public relations.

MR. CHAIRMAN: The time is over.

SHRI RAHUL BAJAJ: But it is of understanding today, it is of envisioning a better tomorrow and having the confidence in oneself and of one's team to make our future happen. Leaders are those that deliver better outcomes. Occupying a chair does not make us a leader.

Sir, Gandhiji occupied no chair but led the country from subjugation to freedom, striding like a colossus in our hearts and minds. We will do well, may I say so, Sir, in all humility, to remember Gandhiji's teachings of the seven social sins - wealth without work, pleasure without a conscience, education without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice and politics without principles.

MR. CHAIRMAN: This is very good, but the time is over.

SHRI RAHUL BAJAJ: In my view, precisely, because we have ignored these teachings that we have under-achieved. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: आप को maiden speech के हिसाब से टाइम दिया है। अब 18-20 मिनट हो गए हैं।

SHRI RAHUL BAJAJ: Sir, just give me two-three minutes more. In this august House, I will endeavour in all humility to play the role that the Constitution envisaged each Member to play. That is, on behalf of the people of India, hold the Government accountable. No more, no less. We have enough good laws. What we lack is speed and justice in their implementation. I would like to consider myself as representing a large political spectrum. Three of the four major parties in Maharashtra supported me as an independent; and my family is steeped in the Gandhian culture, and this gives me a lot of pride. So, I will try to be even handed as an independent, with right and wrong for the country being the sole yardstick for holding an opinion, though I may be mistaken sometimes.

In conclusion, Sir, coming into this august House, I am conscious of my responsibilities to the nation. Panditji's "Tryst with Destiny" reverberates inside my mind. I have come here to try to help in all humility, redeem the pledge that was taken by our founding fathers. So, may God give me the strength to make a difference! I get a strong feeling, Sir, that I can bank on the bipartisan support of both sides of this august House. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much for your maiden speech. माननीय सदस्यगण, अभी एक Half-an-Hour discussion है, उसे बीच में लिया जाए या इस debate को continue किया जाए?

श्री विजय जे0 दर्डा (महाराष्ट्र): सर, continue करिए।

श्री दत्ता मेघे : सर, continue करिए।

SHRI RAMDAS AGARWAL (Rajasthan): Sir, on an earlier occasion, it was decided in the House that the Half-an-Hour Discussion will be taken up at 5'o clock, and after that, the debate will be continued.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : माननीय सभापति जी आज की रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस में 5 बजे का समय Half-an-Hour discussion के लिए निर्धारित है। अगर सदन सहमत हो तो यह 5 बजे लेकर उस के बाद एक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का स्टेटमेंट है और फिर हम यह डिस्कसन continue कर सकते हैं? स्टेटमेंट पहले ले लें।

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): सर, विषय की continuity खत्म होती है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the discussion on the Special Economic Zones is also very important.

श्री सभापति : आप की राय ले रहे हैं, क्या करना है?

SHRI V. NARAYANASAMY: दोनों important हैं। It will be over within half-an-hour.

STATEMENTS BY MINISTER - Contd.

Factual position on carrying of Arab TV Channels

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYARANJAN DASMUNSI): In order to strengthen the mechanism of regulation over the content of television channels, which are being transmitted/ re-transmitted through cable networks / DTH in India, for public viewing, the Government has notified Downlinking Guidelines on 11th November, 2005.

All private TV channels, which are beamed into India, and are being transmitted/ re-transmitted through cable networks / DTH in India, for public viewing, have to get themselves registered under the said Guidelines. To facilitate smooth implementation, six months time (upto 10th May, 2006) was provided to all TV channels to comply with the provisions of the Downlinking Guidelines and get themselves registered.

Further, *vide* notification dated 11th May, 2006, the Government allowed the channels which were uplinked from abroad and had made an application for registration to the Central Government upto 11th May, 2006, for a period of six months, *i.e.*, upto November, 2006 or till such registration has been granted or refused.

The private TV channels, which were uplinking from India, in accordance with the permission for uplinking granted before 2nd December, 2005, were treated as "registered" television channels under the Downlinking Guidelines.

It has been brought to the notice of Ministry that some small section of media has reported that India has "banned" Arab TV channels under pressure from Israel. The Government of India denies this vehemently as it is contrary to facts. No channel in particular has been "banned" recently by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of